



04 - प्राकृतिक संपदा को
बचाना मतलब
मानवता बचाना



05 - पर्यावरण की सुरक्षा
करना हर हाल में जरूरी

A Daily News Magazine

इंदौर
सोमवार, 27 जुलाई, 2026



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 295, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - बरसात के मौसम
में लीक से अलीक
तक



07 - औद्योगिक कार्यप्रणाली
और रोजगार के
अवसरों से हुई रुबरु



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

चलते थे नंगे पांव,
अलंगें ही ठीक थीं।
सड़कें बिछीं तो गांव की
क्यारी निगल गई।।
पुरखों के खेत कौड़ियों में
बिक गए, वो भी।
आधी 'बीमारी',
आधी 'उधारी' निगल गई।।
भाई की ऐसे भाई से,
छूटी हथेलियाँ।
भैयारे पे भारी 'गोतियारी'
निगल गई।।
बचपन निगल गया
मेरा दिन चार का यौवन।
मासूमियत को कोई
'खुदारी' निगल गई।।
शोकत दिखा रहे थे
वो हमको गुरूर से,
आतिथ्य को दौलत की
खुमारी निगल गई।
अपनत्व खा गए सभी
ईर्ष्या के पुलिंदे,
रिश्वतों को शिकायत की
पिटारी निगल गई।
अब रुठे की 'खुशांमदें'
की भी नहीं जातीं।
सब मान-मुनव्वल
मनुहारी निगल गई।।
पलकों पे पल रहे थे
ख्वाब एक उम्र से।
कन्धों की जिम्मेदारियाँ
सारी निगल गई।।

- पियूष प्रणव सुमित

फोर्स का इस्तेमाल तय मानकों के मुताबिक नहीं हुआ

सीजेपी के संसद चलो मार्च पर आई आरएफ की रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। 20 जुलाई को कॉन्फ्रेंस जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज और तीन प्रदर्शनकारियों के पेटलेट गन से घायल होने के मामले में सुरक्षा एजेंसियों के भीतर से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएफ) की महानिरीक्षक (डीजी) सीमा धुंधिया ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारियों पर किया गया बल प्रयोग निर्धारित मानकों और आरएफ की ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं था। 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात कंपनी कमांडरों और कमांडेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक



उच्चस्तरीय बैठक में डीजी सीमा धुंधिया ने माना कि उस दिन फोर्स ग्रेडिएंट यानी परिस्थिति के हिसाब से कदम दर कदम बल प्रयोग करने में गंभीर चूक हुई है। आंतरिक समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और भविष्य के लिए

दिशा-निर्देश जारी किए गए। डीजी सीमा धुंधिया ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन जवानों का तबादला हाल ही में जम्मू-कश्मीर या दूसरे स्पेशल ऑपरेशन (आतंकवाद रोधी/उग्रवाद रोधी) क्षेत्रों से हुआ है।

मीराबाई चानू की स्वर्णिम हैट्रिक

ऐतिहासिक प्रदर्शन,भारोत्तोलन में गोल्ड जीतकर भारत को दिलाया गौरव

नईदिल्ली (एजेंसी)। मीराबाई चानू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध की, जो उनके करियर का तीसरा सीडब्ल्यूजी गोल्ड है। खेल और वलीन एंड जंज क्रीडों में नए रिकॉर्ड स्थापित करना उनके निरंतर उच्च प्रदर्शन और शारीरिक क्षमता के विशेषण को दर्शाता है। ग्लासगो में रविवार को महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर मणिपुर की साइडिंग मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया।



पेपर लीक के खिलाफ आज संसद में आ सकता है बिल

जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे, 10 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आवासन के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है।



स्पेशल टास्क फोर्स

और फास्ट ट्रैक कोर्ट

बिल में दो नई धाराएं 12ए और 12बी जोड़ी गई हैं। इसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसआईटी को केंद्र सरकार द्वारा मामला सीपी जांच के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी।

प्रसंगवश

प्रवीण

वी | ते कुछ वर्षों में साउथ एशिया में एक शब्द जिसकी गुंज काफी सुनने को मिली है, तो वह है: जेन जी। जेन जी वह पीढ़ी है, जिसने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता को बदलकर रख दिया। पिछले दो महीनों में जेन जी भारत की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बनकर उभरी। नीट-यूजी का पेपर लीक होने के बाद भारत के जेन जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉन्फ्रेंस जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुवाई में जेन जी का आंदोलन शुरू हुआ। चूंकि इस आंदोलन की अगुवाई सीजेपी कर रही थी, इसलिए शुरुआत में विपक्षी दलों ने भी इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन बीते एक हफ्ते में जेन जी का यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि तमाम विपक्षी दलों को इसका साथ देना पड़ा। यह इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया।

बीते 12 वर्षों में मोदी सरकार एक बात को अपनी मजबूती की तरह दिखाती थी। लेकिन जेन जी ने मोदी सरकार की इस यूएसपी को ब्रेक कर दिया है। जेन जी के आंदोलन की मुख्य मांगों को मोदी सरकार ने स्वीकार किया। कैबिनेट से केंद्रीय मंत्री के इस इस्तीफे के साथ ही कॉन्फ्रेंस जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया। लेकिन जिस कामयाबी के साथ जेन जी का यह आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद यह सवाल निकलना लाजिमी है कि यहां से भारत की राजनीति किस ओर रुख करेगी और उसमें जेन जी की क्या भूमिका होगी।

आंदोलन पर नजर रखने वाले और उसे कवर करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेन जी के

इस आंदोलन की छाप आने वाले कई वर्षों तक भारत की राजनीति पर देखने को मिलेगी। 20 जुलाई के बाद से ही जंतर-मंतर पर जो कुछ देखने को मिला, वह कई मायनों में भारत में पहले हुए आंदोलनों से अलग था। जेन जी के विरोध प्रदर्शन में बेबाक नारे, पोस्टर, गाने, डांस, धूप या बारिश में डूटे रहने का हैसला तो था ही। साथ ही, डिलीवरी ऐप्स का जिस तरह इस्तेमाल देखने को मिला, वह अपने आप में ऐसी जगह पर संसाधन जुटाने का नया तरीका दे गया, जहां टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना डूटे रहने को बेहद मुश्किल बनाता है।

आंदोलन के पहले दिन से इसकी गवाह रहीं स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा कहती हैं, 'जो आज हुआ है, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अहम क्षण है, क्योंकि इसमें एक बहुत जरूरी कोर्स कंवेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र और उसमें लोगों का विश्वास भी क्रायम हुआ है।'

भारत के सोशल स्ट्रक्चर से अलग, इस आंदोलन ने शिक्षा के मुद्दे पर जेन जी को एकजुट किया। इस आंदोलन में जिसकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी, वे थे स्कूल-कॉलेज के छात्र और अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लड़के-लड़कियां। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक विजय त्रिवेदी कहते हैं, 'जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल बॉक्स हैं, जाति और धर्म से अलग होकर यह आंदोलन था और बिना किसी राजनीतिक दल के मोटे तौर पर सहयोग के, यह अपने आप खड़ा हो गया। बिना किसी के कॉल किए, वे लोग अपने आप आकर खड़े हो गए। और सब राजनीतिक दलों को जगा भी दिया और दबाव में भी ला दिया। सत्तापक्ष

तो, जाहिर है, दबाव में आ ही गया कि मंत्री का इस्तीफा हो गया और विपक्ष को भी दबाव में ला दिया कि सभी लोग एकजुट होकर करीब-करीब उनके साथ आ गए।'

वहीं वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। जेन जी का आंदोलन ऐसा सवाल था, जो सरकार के लिए 'आउट ऑफ सिलेबस' का सवाल बनकर आ गया। उसे हल्के में लिया गया। लेकिन यह सरकार पर उल्टा पड़ गया।

इंस्टाग्राम वह प्लेटफॉर्म है, जिसे जेन जी का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। इस आंदोलन का भी सबसे ज्यादा प्रभाव इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला। बीते एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर जंतर-मंतर से जुड़ी रील्स की बाढ़ आ गई थी। इंस्टाग्राम चलाने वाले अधिकतर यूजर्स आंदोलन से जुड़ी रील्स के बारे में ही बातें करने लगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले गुरुवार और फिर शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट कीं। इस आंदोलन से राजनीतिक दलों को क्या सबक मिलता है, इस बारे में बात करते हुए स्मिता शर्मा कहती हैं, 'बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है, जिसने 2013 से, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही, अपनी कैपेन के नैरेटिव बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात स्थापित हो गई कि आप सोशल मीडिया पर दिनभर अगर एकतरफा नैरेटिव देंगे, तो एक वक्त ऐसा आता है, जब पानी फिर से ऊपर चला जाता है और वही हुआ।' आदेश रावल कहते हैं, 'इस आंदोलन में छात्रों ने मोदी सरकार को इंस्टाग्राम पर

हरा दिया। यानी सरकार छात्रों से डरी। हर रोज की जो फ्रीड थी, उससे भी वह घबराई। जेन जी ने सरकार को झुकाकर दिखाया।' स्मिता शर्मा मानती हैं कि विपक्ष के लिए भी मैसेज है कि लड़ाई सोशल मीडिया से आगे सड़क पर लड़ी जाती है।

यह सवाल भी है कि अब जेन जी की भारत के राजनीतिक भविष्य में क्या भूमिका होगी?

विजय त्रिवेदी कहते हैं, 'अभी तक, अगर हम पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखें, तो उसमें दो-तीन तरह के वोट बैंक रहे हैं। एक वोट बैंक पिछड़ों और गरीबों का था। राजनीतिक दल उन्हें चीजें दे रहे थे, लैपटॉप दे रहे थे। फिर दूसरा दौर आया, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक दलों ने वोट बैंक बनाया। अब इस आंदोलन ने यह फोकस तय कर दिया है कि अगले चुनावों का वोट बैंक युवा होंगे। आदेश रावल जेन जी के आंदोलन को भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार के इस दौर में, जहां इतना डर था, वहीं जेन जी के इन युवाओं ने पिछले पांच दिन में मोदी सरकार का इकबाल खत्म कर दिया। कैसे-कैसे स्लेगन्स, कैसे-कैसे नारे और मीम्स चलाए गए, दिखाए गए और बताए गए। वो भी पुलिस के सामने। तो मुझे लगता है कि यह एक नई शुरुआत है।'

स्मिता शर्मा कहती हैं, 'इस आंदोलन का इलेक्टोरल आउटकम सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद बस यही की जा सकती है कि कम से कम जो युवा पॉलिटिकली जागरूक नजर आए हैं। नीतियों को बदलना होगा, तो राजनीति पर नजर रखनी होगी।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत

पीएम ने आईएनएस महेन्द्रगिरि और पिनाका रॉकेट प्रणाली का किया जिक्र

कहा-इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों-इंजीनियरों की सामूहिक मेहनत है

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश अपने सशस्त्र बलों के साहस के साथ-साथ अपनी तकनीकी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने आईएनएस महेन्द्रगिरि, पिनाका रॉकेट प्रणाली और कुशा मिसाइल का जिक्र कर भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने भारतीय नौसेना में आईएनएस महेन्द्रगिरि के शामिल होने को स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में भारत की प्रगति के उदाहरण के रूप में बताया। पीएम मोदी ने आईएनएस महेन्द्रगिरि की खूबियां बताते हुए कहा कि यह आधुनिक युद्धपोत भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है।



प्रधानमंत्री ने पिनाका का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (एलआरजीआर - 120) का भी जिक्र किया, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक उन्नत सटीक निर्देशित तोपखाना रॉकेट प्रणाली है। इस प्रणाली की प्रमाणित मारक क्षमता 60 किमी से 120 किमी तक है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सामूहिक मेहनत है। प्रधानमंत्री ने कुशा मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण पर भी प्रकाश डाला और इसे भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक और मील का पत्थर बताया।

तमिलनाडु में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट

तीन लोगों की मौत,अन्नामलाई ने की निष्पक्ष जांच की मांग

विरुधुनगर (एजेंसी)। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास रविवार सुबह एक पटाखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार, शिवकाशी के निकट एक टिन शेड में कथित तौर पर अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम चल रहा था।

ओरछा में रामराजा के दर्शन के बाद निवाड़ी पहुंचे सीएम

कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का लोकार्पण किया

निवाड़ी (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का निवाड़ी दौरा जिले के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। ओरछा में भगवान रामराजा सरकार के दर्शन और रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री निवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया एवं ओरछा के जहांगीर महल का भ्रमण किया। बुदेलखंड के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आन-बान-शान के लिए इस वीर भूमि ने हमेशा डटकर मुकाबला किया है और अब सरकार यहाँ विकास की नई इबारत लिख रही है।

कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का लोकार्पण- मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर लगभग रु. 2,563 करोड़ की लागत से बने नवीन



संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट भवन और करीब 1,998 करोड़ की लागत वाले 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 110 करोड़ की लागत वाले 44 अन्य विकास कार्यों की सीगात भी जिले को मिली। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रों बच्चों को टाइसाइकिल और डिब्बाओं को साइकिलें वितरित कीं। मंच पर पारंपरिक रूप से कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन भी किया गया।

साथ में मौजूद रहे स्थानीय नेता- मुख्यमंत्री के इस दौर के दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, जिलाध्यक्ष राजेश पटेलिया निवाड़ी विधायक अनिल जैन सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

केन-बेतवा परियोजना

से बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि रु. 1 लाख करोड़ की इस योजना से निवाड़ी के 158 गांवों को पानी मिलेगा, जिससे क्षेत्र से पलायन रुकेगा। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। यह दौरा निवाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ बुदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक बड़ा संदेश दे गया।

निवाड़ी को मिली कई नई घोषणाएं

क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन की मांगों पर त्वरित कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सिमरा खास में सॉदीपनि विद्यालय खोलने, निवाड़ी और पृथ्वीपुर में गीता भवन निर्माण, जनौली-चंदवनी मार्ग पर पुल, निवाड़ी में आधुनिक बस स्टैंड और तरीचरकला में गौशाला निर्माण की घोषणा की। इससे पहले विधायक अनिल जैन ने काव्यात्मक अंदाज में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए निवाड़ी के विकास को नई दिशा देने के लिए आभार जताया।

सरोकार
डॉ. चन्दर सोनाने

उज्जैन के एक वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री कृष्णकुमार अटल ने इंदौर गेट स्थित उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर प्रस्तावित केबल कार (रोपवे) स्टेशन के निर्माण के स्थान पर पुनर्विचार करने और उस स्थान को रेलवे पार्किंग के लिए सुरक्षित रखने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय रेल मंत्री को एक पाली लिखी है।

पिछले सप्ताह लिखी इस चिट्ठी में श्री के.के. अटल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री को निवेदन किया है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन के इंदौर गेट स्थित प्रवेश द्वार के बाहर पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार इस स्थान पर महाकाल कॉरिडोर हेतु केबल कार

संक्षिप्त समाचार

सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के बहाने सपा पर कसा तंज

- कहा-केसरिया कपड़े से तो सपा को जैसे लगता है जन्मजात दुरमनी हो



इटावा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इटावा में रविवार को आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने कहा- पहले समाजवादी पार्टी कहती थी, कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख

नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी है। सभा में उपस्थित जनता को सावधान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो लोग आएंगे, फिर से कालरात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। ये लोग पहचान का संकट खड़ा करेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे।

स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया

- राहुल गांधी का सरकार से सवाल, शाह को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें राहुल ने दो सवाल पूछे हैं। पहला- प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया। दूसरा- सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, वे पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स उनकी तैनाती किसने की। राहुल ने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स से बात करने के बजाय सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कड़ियों के निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया।

19 साल के छात्र साहित्य लोचब की एक आंख चली गई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉन्फिक्चर जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका जेपी नड्डा से मिले और उनके सामने देश में शिक्षा सुधार के लिए 5 मांगें रखीं। इनमें पेपर लीक मामलों में 10 साल की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त करने, नया नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाने और नियुक्तियों की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की था। राहुल ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं।

उज्जैन के वरिष्ठ नागरिक द्वारा रेलवे की पार्किंग बचाने के लिए पहल

स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं इस योजना के उद्देश्य का पूर्ण सम्मान करता हूँ तथा महाकाल नगरी में आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विकास का स्वागत करता हूँ। तथापि, मेरा विनम्र निवेदन है कि केबल कार स्टेशन के लिए इस स्थान का चयन पुनर्विचार योग्य है। उज्जैन के इस वरिष्ठ नागरिक ने इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित बताएं हैं –

- रेलवे स्टेशन की प्राथमिक आवश्यकता पार्किंग है। उज्जैन आने वाले यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर उपलब्ध यह खुला स्थान पार्किंग एवं यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अधिकांश यात्री सीधे महाकाल मंदिर नहीं जाते। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अधिकांश

श्रद्धालु पहले अपने होटल, धर्मशाला अथवा निवास स्थान पर जाकर सामान रखते हैं, स्नान-विश्राम करते हैं और उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। इसलिए रेलवे स्टेशन से सीधे केबल कार की उपयोगिता सीमित रहेगी।

- रेलवे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी। यदि केबल कार स्टेशन रेलवे स्टेशन के बाहर

प्रदेश के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी

बनाया जाता है, तो ऐसे लोग भी वहाँ पहुँचेंगे, जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं होगा। इससे रेलवे स्टेशन परिसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

- यातायात एवं पार्किंग की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। रेलवे यात्रियों, टैक्सी, ऑटो, निजी वाहनों तथा केबल कार उपयोगकर्ताओं की संयुक्त आवाजाही से ट्रैफिक जाम एवं

अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।

- भविष्य की दृष्टि से यह स्थान अत्यंत मूल्यवान है। रेलवे स्टेशन के आसपास खुली भूमि भविष्य में पुनः उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः इस स्थान का उपयोग केवल रेलवे से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सुरक्षित रखा जाना अधिक दूरदर्शी निर्णय

होगा।

श्री अटल ने इस संबंध में अपने सुझाव देते हुए लिखा है कि केबल कार परियोजना निश्चित रूप से जनहित की योजना है। परंतु उसका स्टेशन किसी ऐसे स्थान पर विकसित किया जाए, जहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। यातायात का दबाव कम हो तथा रेलवे स्टेशन की कार्यप्रणाली

प्रभावित नहीं हो। रेलवे स्टेशन के बाहर उपलब्ध संपूर्ण खुला क्षेत्र रेलवे पार्किंग, ड्रॉप-ऑफ जोन, बस-टैक्सी प्रबंधन तथा भविष्य के यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए आरक्षित रखा जाए। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री और रेल मंत्री भारत सरकार इस विषय पर तकनीकी एवं यातायात विशेषज्ञों से पुनः अध्ययन करारक जनहित में उचित निर्णय लेंगे।

वरिष्ठ नागरिक श्री के.के. अटल ने रेलवे पार्किंग को सुरक्षित रखने के संबंध में जो पहल की है, वह सराहनीय है। उन्होंने स्थान परिवर्तन के जो प्रमुख कारण बताएं हैं वे भी अत्यन्त गंभीर और विचारणीय है। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री और रेल मंत्री उनके सुझाव पर गंभीरतापूर्वक सोच-विचार कर जनहित में निर्णय लेंगे।

अंग्रेजी के ‘ए’ ने खोला राज, जिसे एक्सीडेंट समझा

वो निकली खौफनाक हत्या की साजिश, एक के चक्कर में ली 5 बेकसूरों की जान



नरसिंहपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। शुरुआत में जिसे पुलिस एक सामान्य और दर्दनाक सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही थी, वह असल में एक सुनियोजित मर्डर प्लॉट निकला। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों (टेक्निकल एविडेंस) ने इस पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी हैं।

नरसिंहपुर के एसपी ऋषिकेश मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह साजिश सिर्फ एक शख्स को रास्ते से हटाने के

लिए रची गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि उस टारगेट के पास खड़े पांच अन्य लोगों की भी इस खूनी खेल में जान चली गई। जो घटना पहले महज एक सड़क हादसा लग रही थी, वह पुलिस की कड़ी जांच के बाद एक सोची-समझी हत्या की साजिश साबित हुई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपी राजेंद्र और आनंद पटेल के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोप है कि इस दुश्मनी को पूरा करने के लिए राजेंद्र पर लगातार नजर रखी जा रही थी।

शिवपुरी में टीआई ने 50 के स्टाम्प पर लिखा

आजीवन न नशा लूंगा और न गाली दूंगा, नियम तोड़ा तो छोड़ दूंगा नौकरी

शिवपुरी (नप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से पुलिस महकमे के भीतर से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायी खबर सामने आई है। यहां के अजाक थाने के प्रभारी आचार्य डॉ. रणजीत सिंह रघुवंशी ने समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। उन्होंने पूरी तरह स्वेच्छ से आजीवन नशामुक्त और गाली-मुक्त जीवन जीने का कड़ा संकल्प लिया है।

डॉ. रघुवंशी ने 23 जुलाई 2026 को 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर एक ऐतिहासिक शपथपत्र जारी किया है। इस हलफनामे में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि वे चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, मांस, मछली और अंडे समेत किसी भी प्रकार के नशे या व्यसन का सेवन नहीं करते हैं और अपनी अंतिम सांस तक ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्रण लिया है

कि वे जिंदगी में कभी किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्द या गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

नौकरी छोड़ने तक की रख दी शर्त– इस शपथपत्र की सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें खुद टीआई ने अपने ऊपर कड़ा अनुशासन लागू किया है। हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि यदि भविष्य में उनकी किसी भी



घोषणा का उल्लंघन साबित होता है, तो पुलिस विभाग यदि उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी करता है, तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

समाज और पुलिस विभाग के लिए बड़ा संदेश– डॉ. रणजीत सिंह रघुवंशी का यह कदम न केवल पुलिस विभाग के भीतर बल्कि आम समाज के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन गया है। उनका मानना है कि एक पुलिस अधिकारी का आचरण हमेशा समाज के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। जब तक अधिकारी और कर्मचारी खुद संयमित और नशामुक्त जीवन नहीं जीएंगे, तब तक एक स्वस्थ और आदर्श समाज का निर्माण संभव नहीं है। उनकी इस पहल ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो खाकी वर्दी के भीतर रहकर भी उच्च नैतिक मूल्यों को मिसाल कायम की जा सकती है।

संकल्प : एक नजर में

- अधिकारी का नाम– आचार्य डॉ. रणजीत सिंह रघुवंशी (थाना प्रभारी, अजाक थाना, शिवपुरी)
- शपथ की तारीख– 23 जुलाई 2026
- माध्यम– 50 रुपये का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर
- मुख्य संकल्प– आजीवन नशामुक्त, मांसाहार मुक्त और पूरी तरह गाली-मुक्त जीवन
- बड़ी शर्त– नियम टूटने पर पुलिस विभाग द्वारा सेवा से हटाने पर भी पूर्ण सहमति

भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स

रक्षामंत्री बोले-भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा तो पाक घुसपैठ के



नईदिल्ली (एजेंसी)। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। साफ है कि हमारे रास्ते अलग-अलग हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़े खड़े करता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार बैठी हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर

भारत की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी भी, तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। कारगिल वॉर मेमोरियल में पूरा भारत दिखाई देता है। यहां शहीदों में हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, तमिलनाडु समेत देश के हर हिस्से के जवानों के नाम दर्ज हैं। शहीदों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने वाले सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जो लोग देश को बांटने का सपना देखते हैं, उन्हें इस स्मारक की दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार ही भारत को बांटने की उनकी सोच का सबसे बड़ा जवाब है।

ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रम्प

- अमरीकी सेना को कार्गवाई रोकने का दे दिया आदेश

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रम्प ने सेना को नए बड़े हमले रोकने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान और बढ़ाया गया तो मिडिल-ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने सलाह दी कि बड़े अभियान से मिडिल-ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था। एक्सप्रेस के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमले रोकने का फैसला अस्थायी है या लंबे समय तक लागू रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार रहेगी।

प्रधान के एगिजट के बाद प्रल्हाद जोशी की एंट्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर संभाल लिया पदभार



नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक एक दिन बाद रविवार को प्रल्हाद जोशी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। धारवाड़ से पांच बार के सांसद प्रल्हाद जोशी इससे पहले कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पिछले कुछ

वर्षों में, प्रल्हाद जोशी ने कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मंत्री पदों का कार्यभार संभाला है। 2019 से 2024 के बीच उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्य किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री के रूप में, प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों सहित कई प्रमुख सरकारी पहलों की देखरेख की है।

शिक्षा मंत्री के सामने कई चुनौतियां

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही वे अपने मौजूदा मंत्रालयों का काम भी संभालते रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रल्हाद जोशी के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और छात्रों का भरोसा मजबूत करना प्रमुख हैं। गौरतलब है कि शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर किया गया। इसके बाद प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया।

हमारी सनातन संस्कृति प्रकृति की संरक्षक



इंदौर। हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति के उपादानों के प्रति प्रारंभ से ही श्रद्धा निष्ठा अर्चना और आस्था के भाव रहे हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, संरक्षक हैं। प्रकृति की समृद्ध विरासत हमें बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है परन्तु इसे समृद्ध और सशक्त बनाकर भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के लिए है। हमारे कोई भी अनुष्ठान प्रकृति के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। उक्त उद्धार डॉ अशोक कुमार भार्गव (आईएएस) ने माथुर वैश्य समाज संगठन के सौजन्य से शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। इस अवसर पर डॉ भार्गव ने चिंता व्यक्त की कि आज के बदले हुए परिवेश में प्रकृति के प्रति मानवीय दायित्व का पालन करते हुए उसका संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसान की कभी भी समाप्त न होने वाली लालची प्रवृति ने प्रकृति का निर्मम दोहन कर जलवायु परिवर्तन का महासंकट निर्मित किया है। भूजल स्तर निरंतर घट रहा है, हमारी कृषि मौसम पर निर्भर है और मौसम जंगलों पर निर्भर है, किंतु जंगल हम काटते जा रहे हैं। अतः जरूरी है कि हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास अभियान के रूप में करें और खासतौर पर अपने जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, अपने पुर्वजों की स्मृति तथा खुशी के किसी अवसर को यादगार बनाएं! कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेन्द्र चौधरी (आईपीएस) हर्षिता डेविड तथा ओमप्रकाश गुप्ता मंचासीन रहे।

चलते वाहन के पहिए टूटे, वाहन पलटा

इंदौर। सावेर के बरौली गांव स्थित बीएसएफ रेंज के सामने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात बड़ा सड़क हादसा टल गया। इंदौर से नीमच परचून का सामान लेकर जा रहा एक लोडिंग वाहन अचानक पिछले पहियों के सेंटर बोल्ट टूटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ। चालक प्रकाश, निवासी प्रतापगढ़, ने बताया कि वाहन के दोनों पिछले पहिए अलग हो जाने से संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में चालक और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। दुर्घटनाग्रस्त वाहन इंदौर के ग्वालटोली स्थित बाबू ट्रांसपोर्ट का बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं था। यदि उस दौरान सामने या पीछे से वाहन गुजर रहे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद कुछ्दर तक यातायात प्रभावित रहा।

गांजा सप्लायर का साथी भी पकड़ाया

इंदौर। तीन दिन पहले 22 जुलाई को कनाड़िया पुलिस ने गांजा सप्लायर करने वाले दो युवकों को पकड़ा। दोनों युवक ऑटो रिक्शा में एक किलो 757 ग्राम गांजा लेकर जा रहे थे। आरोपियों ने पूछताछ में अपने एक अन्य साथी का नाम बताया था। पुलिस ने 24 जुलाई को फरार साथी को भी दबोच लिया है। 22 जुलाई को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टी.पी.एस.-9 रोड बिचौली हस्सी के पास मौजूद थी। इसी दौरान ऑटो रिक्शा क्रमांक एमपी-09-आरए-5347 में दो व्यक्ति सदिध अवस्था में घूमते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी अनिल पिता मनोहर लाल बौरासी निवासी भागीरथपुरा तथा प्रिंस कोशल उर्फ दादू, पिता सुरेन्द्र कोशल निवासी भागीरथपुरा भागने लगे। लेकिन, पुलिस ने घेराबंदी कर ऑटो रिक्शा को रोक लिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अपने एक अन्य साथी राजेन्द्र उर्फ राजू पिता जगेश्वर गौतम निवासी हनुमान मंदिर के पास इंदौर नाका बड़वाह को 600 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में राजेन्द्र ने बताया कि वह अनिल एवं प्रिंस को गांजा सप्लाई करने उपलब्ध कराता था।

प्रखर सिंह कुशवाह बने असिस्टेंट कमांडेंट

इंदौर। होनहार युवा प्रखर सिंह कुशवाह ने यूपीएससी द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में खुशी का माहौल है। प्रखर के पिता पीएस कुशवाह नगर निगम में सिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। प्रखर ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और परिवार के निरंतर सहयोग के दम पर यह मुकाम हासिल किया। चयन के बाद अब वे निर्धारित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनकी नियुक्ति देश के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। प्रखर की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रही है।

हर थाने में होगी इग डिटैक्शन किट

इंदौर। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में नशे के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब सभी थानों और जोंगों को नारकोटिक्स इग डिटैक्शन किट उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश का पहला पुलिस कमिश्नरेट बन गया है, जहां प्रत्येक थाने में यह आधुनिक जंग किट रहेगी। किट बांटे हुए पुलिस आयुक्त ने बताया कि इन आधुनिक किटों की मदद से एनडीपीएस की धारा में जब्त मादक पदार्थों की जांच मौके पर ही अधिक तेजी, सटीकता और पारदर्शिता के साथ की जा सकेगी। इससे अनुसंधान की गुणवत्ता बेहतर होगी। विवेचना मजबूत बनेगी और पुलिस कार्रवाई की प्रभावशीलता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल नशे के कारोबार पर कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि आधुनिक तकनीक संसाधनों का उपयोग बढ़ाकर तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। पुलिस का मानना है कि तकनीक आधारित जांच व्यवस्था से न केवल मामलों की जांच तेज होगी, बल्कि अपराधियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटने में भी मदद मिलेगी।

गता फैक्ट्री में भीषण आग लगी

इंदौर। सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के ई- सेक्टर में शुक्रवार देर रात गता फैक्टरी में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। पतरे के शेड में बने इस कारखाने में गता और अन्य ज्वलनशील सामान भरा होने से आग तेजी से फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर नियंत्रण पाने में 7 घंटे की कड़ी मशक़त करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि घटना के समय फैक्टरी बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड को रात करीब 2 बजे श्रीराम गता फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। खबर मिलते ही तत्काल तीन दमकों की मोर्के के लिए रवाना किया गया। जब फायर टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पूरा शेड आग की लपटों से घिरा हुआ था। आग की भयावहता को देखते हुए जेसीबी मशीन की मदद से शेड के हिस्सों को तोड़ा गया ताकि पानी अंदर तक पहुंचाया जा सके। सुबह 9 बजे तक चले बचाव कार्य में टीम ने ढाई लाख लीटर पानी का उपयोग कर आग पर काबू पाया।

गंजबासौदा के एक खेत में मिला कटा सिर, अखिलेश सैनी का होने की शंका

ट्रेक से 500 मीटर दूर मिला सिर, डीएनए जांच से होगी पहचान

सिर मिला, वह रेलवे ट्रैक से लगभग 500 मीटर दूर खेतों के बीच स्थित है। सिर की हालत इतनी खराब थी कि उस पर मांस और मांसपेशियां नहीं बची थीं तथा केवल हड्डियों का ढांचा शेष था। इसी कारण मौके पर उसकी पहचान संभव नहीं हो सकी। मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर बीएल मालवीय ने बताया कि खेत से मिले सिर और पहले बरामद धड़ का डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि दोनों एक ही व्यक्ति के हैं या नहीं। यदि डीएनए रिपोर्ट में सिर की पहचान अखिलेश सैनी के रूप में होती है, तो यह उर्मिला सैनी हत्याकांड की जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी।

उर्मिला सैनी की हत्या के बाद से ही आरोपी अखिलेश सैनी फरार चल रहा था। उसकी बेटी प्रेक्षा ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता लंबे समय

नशे के खिलाफ शहर में सबसे बड़ी दौड़, 8100 से ज्यादा आवाज उठी

पुलिस आयुक्त, क्रिकेटर रजत पाटीदार ने लोगों को शपथ दिलाई



जुम्मा से हुई शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत वॉर्कार्थों से पहले आयोजित जुम्मा सेशन से हुई। सभी महिलाओं ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ वॉर्म-अप किया, जिससे आयोजन का माहौल उत्साह और सकारात्मकता से भर गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई।

नारों से लोगों को जागरूक किया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने नागरिकों से नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। वहीं रजत पाटीदार ने

युवाओं से खेल, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की अपील की। दौड़ से पहले प्रतिभागियों ने सामूहिक व्यायाम कर उत्साह के साथ आयोजन की शुरुआत की। समापन पर प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पांडे दंपति की रिहाई के लिए मंत्री विजयवर्गीय ने कमिश्नर को लिखा

इंदौर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के सामने बिना पूर्व सूचना और अनुमति के धरना देने वाली पांडे दंपतिप्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने पांडे दंपति की रिहाई को लेकर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर नियमानुसार कार्रवाई कर रिहा करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि दंपति सोशल मीडिया पर फैलाई भ्रामक जानकारी के कारण भ्रमित होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अब उनके प्रति किसी प्रकार की व्यक्तिगत शिकायत या आपत्ति नहीं है। पत्र के अनुसार, मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था कि मैंने दिल्ली में आंदोलनरत छात्रों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस आरोप का प्रचार किया था। मंत्री ने बताया कि अगले दिन उनके आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच कराई और सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मेरे द्वारा कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई थी। इस क्रम में इंदौर निवासी



प्रहलाद पांडे और उनकी पत्नी भी प्रदर्शन करने पहुंचे। चूंकि प्रदर्शन की पूर्व घोषणा की जा चुकी थी, इसलिए पुलिस पहले से सतर्क थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने नियम के अनुसार कार्रवाई कर दंपति को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

सत्र के बाद मिली जानकारी

मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि घटना के समय वे विधानसभा की कार्रवाई में व्यस्त थे। सत्र समाप्त होने के बाद उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। बाद में यह भी पता चला कि संबंधित दंपति के दो छोटे बच्चे हैं। माता-पिता की गलती का असर मासूम बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि यदि कानून और नियमों के तहत संभव हो, तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पांडे दंपति के मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए।

‘मेट्रो’ और ‘एमआर-10’ बस टर्मिनल संचालन साथ शुरू

17 किमी का मेट्रो कॉरिडोर तैयार, स्टेशन से 500 बसों का संचालन



टर्मिनल से प्रतिदिन लगभग 500 बसों का संचालन प्रस्तावित है। यहां से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के लिए नियमित बस सेवाएं संचालित होंगी। अनुमान है कि इस बस स्टेशन से रोजाना 25 हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही होगी। इनमें बड़ी संख्या ऐसे यात्रियों की होगी जो शहर के अलग-अलग

अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं। इसी कारण दोनों परियोजनाओं को एक साथ शुरू करने की रणनीति बनाई जा रही है। नए बस स्टेशन के संचालन की जिम्मेदारी इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक निजी कंपनी को सौंप दी है। इसके बाद स्टेशन को चालू करने की प्रशासनिक

से उसकी मां पर बिना किसी आधार के शक करते थे। उसने यह भी खुलासा किया था कि आरोपी पहले भी उर्मिला का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास कर चुका था। एक बार जब उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, तब अखिलेश ने मंदिर का सिंहासन उठाकर उसी पर फेंक दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों लगातार तलाश में जुटी थीं। पहले उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अखिलेश पिछले 8 दिनों से कहाँ छिपा हुआ था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।

पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर की सदिध मौत, पति-ससुर पर आरोप

फांसी के बाद इलाज के दौरान मौत, सुसाइड नोट नहीं मिला

इंदौर। पलासिया थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर की सदिध मौत का मामला तूल पकड़ गया। शुक्रवार को फांसी लगाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई 40 वर्षीय आरती यादव ने शनिवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति और ससुर पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरती यादव पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थीं और सरकारी आवास में रहती थीं। घटना के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, इसलिए पुलिस मौत के कारणों की हर पहलू से जांच कर रही है।

शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल और थाने पहुंच गए थे। आरती के भाई उषेंद्र ने पलासिया पुलिस को दिए बयानों में आरोप लगाया कि उनकी बहन और जीजा के बीच लंबे समय से पारिवारिक तनाव और अनबन चल रही थी। दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर कहसुनी और विवाद होता रहता था। पुलिस के मुताबिक, आरती का मायका सुखलिया में है। जबकि, उनका ससुराल



झाबुआ जिले में है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मृतका के परिजनों ने बताया कि आरती की शादी वर्ष 2012 में नीलेश यादव से हुई थी, जो स्वयं भी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। मायके पक्ष का आरोप है कि पति लंबे समय से आरती को त्राउंडित करता था। मृतका के भाई ने पति पर हत्या करने और ससुर को पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस परिजनों और मृतका की बचियों के बयान दर्ज कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

कनाड़िया पुलिस को अपनी कोशिश में सफलता मिली



सोनोने निवासी अजयबाग कॉलोनी, मूसारखेड़ी तथा नीतेश पिता मदन प्रजापति निवासी पारसी मोहल्ला को

पकड़ा। तीनों आरोपी हुंडई कार से राऊ बायपास पर खड़े थे। कार से भी पुलिस ने 15 पेटी शराब जब्त की है। आरोपी विजय पर राऊ थाने में धारा 294, 506, 406, 420, 34, शिप्रा थाने में धारा 406, 411, 420, टोंकखुर्द थाने में धारा 406, 420, क्राइम ब्रांच थाने में धारा 34(2) जब्तकारी घटने, कनाड़िया थाने में धारा 34(2) तथा दीपेश पर थाना आजाद नगर में धारा 323, 294, 506, 34,थाना कनाड़िया में धारा 34(2), आरोपी नीतेश पर थाना संयोगितागंज में धारा 323, 294, 506, 34 के केस दर्ज हैं।

एक्टिवा से मिली शराब

उधर, आबकारी विभाग भी नशे से दूरी है जरूरी अभियान में कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने महु नाका क्षेत्र से एक्टिवा क्रमांक एमपी-09-ईए-9382 को रोका। चेक करने पर एक्टिवा की डिब्की से 2 पेटी बैगपाइपर व्हिस्की, एक पेटी लंदन प्राइड व्हिस्की जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक्टिवा सवार युवक भाग निकला। जब शराब और वाहन की कीमत एक लाख 23 हजार 200 रुपए है। विभाग के सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी ने बताया कि तस्करों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगी।

तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं।

लोकार्पण बार-बार स्थगित

गांधी नगर से रेंडिसन चौराहा तक 17 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण भी पूरा हो चुका है। करीब दो महीने पहले इसके लोकार्पण की तिथि तय कर दी गई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इसके कारण पूरे कॉरिडोर पर यात्री सेवा शुरू नहीं हो सकी। अब इस मार्ग पर संचालन शुरू करने से पहले रेलवे सेप्टी (सीएमआरएस) की मंजूरी आवश्यक है। मेट्रो कॉर्रोरेशन इस संबंध में आवेदन पहले ही प्रस्तुत कर चुका है। फिलहाल मेट्रो ट्रैक का सुरक्षा परीक्षण होना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा परीक्षण और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग दो महीने का समय लग सकता है। इसके बाद ही गांधी नगर से रेंडिसन चौराहा तक पूरे मार्ग पर मेट्रो का नियमित संचालन शुरू हो सकेगा।

संपादकीय

प्रधान के इस्तीफे की अंतर्कथाएं

अब पूर्व हो चुके केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. धर्मदेव प्रधान के कांकोरोजों के दबाव में इसीफाा देने की अंदरूनी इहानियां सामने आने लगी हैं। बताया जाता है कि प्रधान स्वयं दो बाद इसीफाा की पेशकश कर चुके थे, लेकिन उसे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि तयापत्र का मलबज जिम्मेदारी से भागना होगा। मोदी सरकार और भाजपा का यह आकलन ही उसके गले की हड्डी बन गया और छत्र आंदोलन सुरुसा की तरह फैलता चला गया। इसीफाा के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर आंदोलनकारी जेन जे को आश्चर्य करने की तीस शर्तों की, लेकिन उसमें भी बात नहीं बनी। उल्टे आंदोलनकारियों की कोन प्रमुख मांगों में मंत्री के इसीफाा की मांग ही मुख्य थे गई। अंत में प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और आरएसएस की भी मानना था कि अगर अभी इसीफाा नहीं हुआ तो पूरा मामला हथ से निकल जाएगा। आईबी की रिपोर्ट भी यही कह रही थी। सरकार को चिंता इस बात की थी कि अगर यह आंदोलन नेवल की तर्ज पर हिंसक और बेकाबू हो गया तो भारी नुकसान होगा, सरकार की बदनामी होगी, सो अलग। इसके पहले सरकार ने आंदोलन में फूट खलने की कोशिश भी की। अमरण अनशन कर रहे सोमन वांगचुक के साथ सलथ से बात कर समझौता क्रिया गया, लेकिन आंदोलन के सूत्रधार अभिजित दीपके से कोई पल्ल नहीं की गई। एबीवीपी के छात्रों को भी आंदोलन में शामिल करने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी नाकाम रही। दूसरी तरफ आंदोलन और तेज होता गया। दूर दराज से लड़के-लड़कियां इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। विपक्षी पार्टियों में भी आंदोलन को पूरा समर्थन दे दिया। हलांकि आंदोलनकारी छात्रों ने विपक्ष को अपना कम हार्दिक नहीं करवाया। राहुल गांधी तो अंत तक जंतर मंतर नहीं गए। आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भावगत ने आंदोलनकारियों से बात करने का इशारा किया। बताया जाता है कि धर्मदेव प्रधान का इसीफाा होगा, यह जानकारी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की थी। सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहे केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह को भी इसकी जानकारी बाद में मिली। इससे पहले किसान आंदोलन के हिंसक होने के बाद सरकार ने बिल वापस लिए थे। आंदोलनकारियों के सामने झुकने का ये दूसरा मौका है। आंदोलनकारी युवा प्रधान के इसीफाा को सरकार का झुकना बता रहे हैं तो भाजपा के सूत्री का कहना है कि यह इसीफाा सरकार की रणनीति का हिस्सा है। यानी दो कदम आगे जाने के लिए एक कदम पीछे खींचने की रणनीति। जहां तक इसीफाा की बात है तो किसी आंदोलन के दबाव में ऐसा पहली बार हुआ है। यहां तक कि आंदोलन के बाद सरकार ने तीन विवादित कृषि कानून वापस लिए थे, लेकिन इसीफाा किसी का नहीं हुआ था। बहरहाल आंदोलन समाप्त हो गया है। आंदोलनकारी छात्र अपने सपों को लौट गए हैं। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार छात्रों की बाकी दो मांगों का क्रियान्वयन कर और कैसे करती है। इन दो मांगों में छात्रों पर लाटियां बरसना वेल फुलस कमिश्नय पर कारंवां इथा नीट पेपर लीक होने के बाद हठासा में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रू. का मुआवजा देना शामिल है। अगर सरकार इन वादों से मुकुरी तो जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है। मोदी सरकार ही क्या, कोई भी सरकार युवाओं को इस तरह नाराज नहीं कर सकती। क्योंकि आने वाले कई सालों तक बोटे रहने वाले हैं। दूसरे, जो मुद्दा छात्र उठा रहे थे, वो बिबुलत जायज था।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी
विचारक हैं।



त दाता गुप के मौलिक उद्योगपति श्री अनिल अग्रवाल ने मासिक मीडिया एक एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने देश में कुछ समय पूर्व से हो रहे तेल के संकट को अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण हो रहा था, का उल्लेख करते हुए दुख व्यक्त किया, और लिखा है कि एक ऐसा युद्ध जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, उसकी कीमत देश को भरतील की कमी के चलते उठाना पड़ी है। उन्होंने यह एक वाजिब सवाल उठाया है कि हम देश को जरूरत का 90 प्रतिशत तेल, 95 प्रतिशत कॉपर, 97.5 प्रतिशत सोना निरेश से क्यों आयात करते हैं, जबकि धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि 40 साल इस उद्योग में काम करते हुए वे बेहतरीन हैं। इसी लेख में उन्होंने अपने जीवन को उद्धृत करते हुए बताया है कि 19 वर्ष की उम्र में वे बिहार से मुंबई आये थे, ज़ीरो से कोराबार शुरू किया और उस समय इनके कोई संपर्क नहीं था, कोई गॉडफ़ादर नहीं थे तथा उन्होंने यादें दादना कंपनी ने उसका की निजीकरण योजना के तहत हिंदुस्तान ज़िंक व बालको खरीदा, हालांकि उन्हें दुख है कि इनके शत प्रतिशत शेयर अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। उन्होंने खनिज आत्मनिर्भरता के लिये उन्होंने बड़े पैमाने पर देश के खनिज उत्पादन तेल और गैस के उत्पादन, लोहे का उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

यह तथ्य है कि श्री अनिल अग्रवाल के आर्थिक सम्प्राज्य की वृद्धि श्री अंबानी, श्री अडानी के समान चमत्कारिक हुई है। परंतु उनको दावों व निष्कर्षों की तार्किक पड़ताल जरूरी है। उन्होंने यह नहीं बताया जब वे बिहार से चलकर मुंबई आये थे तो उनके पास कितनी पूंजी थी। सरकार के निजीकरण कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान जिकार व वालको के शेयर खरीदे तब उसके लिए पूंजी कहां से आई और उन कंपनियों के शेयर होल्डर उस जमाने में कौन लोग थे? क्या हिंदुस्तान प्रिजिंट व वालको के क्रमशः 74 प्रतिशत, और 51 प्रतिशत शेयरों से उन्हें मुक्त में प्राप्त हुआ है, जब उनका कोई संपर्क ही नहीं था तो उन्हें इतनी बड़ी धन राशि कहां से प्राप्त हुई? क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनकी करोड़ों की कोई लांछरी खुली हो। आम जनता तो यह है कि देश के प्रांतीय राजनेता और कुछ बड़े उद्योगपति अपने विध्वस्त लोगों

प्राकृतिक संपदा को बचाना मतलब मानवता बचाना

से कारखाने खड़े कराते हैं, उसमें बेनामी शेतास की राशि प्रलंबित है, जो एक प्रकार का निवेश होता है और निरक्षर जिलोंमें प्रीमियम के नाम पर बड़ी-बड़ी राशियाँ लेते रहते हैं, जिससे पूंजी बढ़ती है और राजनैताओं की भारी भ्रमक खर्च भी चलते हैं। श्री अनिल अग्रवाल ने ब्रिटेन से ओजोनजीसी के तेल व गैस के लिये पूंजी प्राप्त की। जापान के मितसुई से सेसा गोवा आयरन अयस्क खरीदा। वे कहते हैं कि हर इस अधिकरण के पीछे एक ही सपना था कि प्रोडक्शन इतना बढ़ाया जाए कि देश आयातक नहीं निर्यातक बन जाये। वे अपनी पीठ यह हक़ार धरथालते हैं कि जब क़ा उत्पादन 10 गुना, एल्यूमीनियम का 20 गुना बढ़ाया जिससे 1000 से अधिक कंपनियाँ खड़ी हुईं और इन 10 वर्षों में वेदांता ने सरकारी खजाने में 4.5 लाख करोड़ रुपया दिया।

श्री अनंत अग्रवाल को मैं बताऊँ कि पिछले लगभग 30-40 वर्षों में जापान और चीन ने भारत को तोले आक्रामक दृष्टि से लोह आक्रामक दृष्टि तथा उसे समुद्रतल के नीचे डुप किया। जबकि उनके पास पर्याप्त लोहा था और उन्हें बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। परंतु ये देश ज्यादा समझदार व राष्ट्रभक्त के हैं उन्होंने अपने देश के खनिजों को सुरक्षित रखने और उनका भंडार बढ़ाने के लिये उपाय किए। वे जानते हैं कि खनिज के भंडार धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे और इसीलिये उन्हें यथा संभव बचाया जाये। परंतु भारत की सरकार वैश्वीकरण के प्रभाव में इतनी प्रस्त रही है कि उन्होंने किसी देश के व्यापक हित को नहीं सोचा। उनसे यह नहीं सोचा कि जो खनिज हम निकालकर बेचेंगे यह देश दोबारा पैदा नहीं होगा। अगर यह खनिज के भण्डार देश में हैं तो देश की प्रकृति की देन है जिसे ईश्वरीय दान के रूप में देना जा सकता है। यह भण्डार न किसी की सरकार ने बनाये और न ही किसी वेदांत ने। आजका आप इन्हें खादकर, उनका निर्यात कर सकते और कुछ संपन्न हो सकते हैं परंतु यह संपन्नता स्थायी नहीं हो सकती। 19वीं सदी में जिन क्षेत्रों में कोयला निकला था उनमें से आज किन्ती ही कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं और स्थिति यह है कि हमें अपनी पूर्ति के लिये कोयला आयात करना पड़ रहा है। देश में जहां-जहां कोयले के भण्डार थे और उनका खनन हुआ निसिंदह सरकार के खजाने में पैसा आया महानगरों में, कारखानों को बिजली पहुंची, उद्योगपतियों की तिजोड़ियां भरी, परंतु जिन गरीबों की जमीन के नीचे कोयला निकला, या जिन, एमपीनिमस, तांबा आदि निकला वह गरीब तो विस्थापन के तंत्रा हो गये। देश के चार छह

उद्योगपति अरबपति से खरबपति बन गये, बीच के दलाल, ठेकेदार और राजनेता करोड़पति बन गये परंतु लगभग 30 करोड़ लोग इस विस्थापन के शिकार होकर, भुखमरी, बीमारी व गरीबी के समुद्र में फेंक दिये गये।

श्री अनिल अग्रवाल की कंपनी का विकास जहाँ राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और केवल पूंजीपतियों के उद्योगपतियों के हक में है परंतु वह देश के लिये अनुकूल नहीं है। वह लिखते हैं कि जिस प्रकार रियाँटिडो और बीएचपी ने आस्ट्रेलिया के विकास के लिये जो भूमिका अदा की वही भूमिका वेदांता भारत के लिये करना चाहता है। रियाँटिडो एक वैश्विक सोसाईटी खदानें खोजने वाला कंपनी है और उसने आस्ट्रेलिया के सोने व खनिजों को खोजकर अपनी पूंजी में लाखों गुना का इजाफा किया है परंतु इससे आस्ट्रेलिया की वास्तविक स्थिति बहुत मजबूत नहीं हुई। चूँकि आस्ट्रेलिया में जमीन अधिक व आबादी कम है और इन खनिज उत्खनन के दुष्प्रभाव पर चर्चा कम हुई, पर वह दिन आने वाला है कि जब आस्ट्रेलिया की सभी खनिज संपदा लुट जायेगी और वह दूसरों का मोहातमा बन जायेगा। श्री अनिल जी कहते हैं कि जब देश में उद्योग तकनीक विशेषज्ञ व वित्त नहीं था तब वेदांता ने विदेश से 35 अरब डॉलर जुटाकर भारत में निवेश किया। अनिल जी जरा बतलिये, 10 सालों में उन्होंने सरकारी खजाने में 4.5 लाख करोड़ दिये हैं, तब वेदांता के खजाने में क्या 20 लाख करोड़ रुपये से कम जमा हुए है? दुनिया के खनिज पूंजीपतियों ने वेदांता के माध्यम से 35 अरब डॉलर की पूंजी लगायी थी, क्या उन्होंने अभी तक 400 अरब डॉलर से कम मुनाफा कमाया है? रियाँटिडो ने आस्ट्रेलिया को न विकसित बनाया, न मजबूत बनाया बल्कि वास्तविक रूप में गरीबी के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। खनिज जो स्थाई संपत्ति होती है वह भी चली गई और लाख एक दो कंपनियों के खाते में पहुँच गया। अनिल जी लिखते हैं कि दुनिया के अधिकांश विकसित देश अपने प्राकृतिक स्रोत से बने हैं जबकि तथ्य यह है कि प्राकृतिक स्रोतों या खनिजों के आधार पर बने विकसित देश कुछ ही दशकों में बर्बादी के मुँह में पँस जाते हैं।

जहां तक उन्होंने दस लाख बैरल तेल प्रतिदिन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसे वह निर्यात भी करेंगे क्योंकि उनकी चिंता तो तेल और गैस के आयात के नाम पर देश को भयभीत करने की है। मेरी राय में तेल के मामले में भी भारत आसानी से आत्मनिर्भर बन सकता है, बशर्ते वह अपने तेल की फिजूलखर्ची कम

करो। जैसा कि हम कहते रहे हैं कि एक परिवार एक कार का कानून बने, अगर वह बन जाये तो देश में औसतन प्रतिदिन 100 करोड़ लीटर व माघ में 3000 हजार करोड़ लीटर और साल में 36000 करोड़ लीटर तेल जिसकी कीमत 36 लाख करोड़ रुपये होगी। वह बच सकता है। हमारे तेल के भण्डार भी खाली नहीं होंगे। अनिल जी कहते हैं कि सरकारों को रेवेन्यू माफेड होना, प्रोड्रेशन माफेड होना चाहिए। याने एक प्रकार से वह उद्योगपतियों की सरकार चाहते हैं जो उत्पादन कर्ताओं को सभी वैधानिक बंधनों से मुक्त करे यहाँ तक कि सरकार की अनुमति के बगैर स्वरूप प्रमाणन की व्यवस्था हो। मेरी राय में सरकारों को न रेवेन्यू माफेड होना चाहिए, न प्रोड्रेशन माफेड, बल्कि उन्हें प्रकृति संरक्षक, खनिज संरक्षक और मानवीय तथा मानवीय विकास की दृष्टि का होना चाहिए। प्रकृति का दोहन न हो, बल्कि न्यूनतम व जरूरी उपयोग के विकास में समानता हो, उन्होंने खुद ही लिखा है कि उनके पारिवारिक गुरु चंचलन के स्वामी शास्त्रानंद जी मानव सेवा संघ में एक छोटी सी कटिया में रहते हैं। उन्होंने उनसे कहा था संपत्ति है, उसे समाज के लिये उपयोग में लाओ और संपत्ति का होने का अर्थ क्या है? एक प्रकार से उन्होंने श्री अनिल अग्रवाल को संकेत दिया है कि जो संपत्ति का संघर्ष किया है, उसे समाज को वापस लौटाओ। मेहनत पूंजीपति भी करते हैं और मजदूर भी करते हैं। पूंजीपति दिमागी मेहनत करते हैं, आम तौर पर भ्रष्टाचार का कौशल अपनाते हैं और उससे अमीर बनते हैं। परंतु मजदूर शरीर का श्रम करता है, पसीना अधिक बहाता है और खुराक व सुविधा कम पाता है। इस विषयमाता को संतुलित करना और मिटाना होगा। हालांकि अपने इसी लेख में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी हौसला अफवाहों को इन शब्दों में दर्ज किया है कि श्रमही भरे जीवन की प्रेरणा है। वे कहते हैं कि श्रमके सुझावों से भारत दुनिया में सर्वोच्च राजस्व देने वाला क्षेत्र बनेगा, सुधार और प्रगति होने से बेरोजगारी दूर होगी, देश आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित राष्ट्र बनाने का माध्यम बनेगा, जैसा कि सपना श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। तथ्य यह है कि प्रगति, प्रधानमंत्री की सपने से बेरोजगारी बढ़ी है, विदेशी कर्ज बढ़ा है, देश तकनीक और अनेकों मामलों में पर निर्भर हुआ है। अशा है अनिल अग्रवाल जी कभी मेरे सुझावों पर भी विचार करेंगे। राष्ट्र के विकास को जो रास्ते महत्वाकांक्षी व डॉ लोहिया जी ने बताये थे, उनको भी अध्ययन और उन पर भी मनन करेंगे।

जंतर-मंतर-आंदोलन

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



अ ततः धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन यह जेन-जी प्रणीत आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति है। यह युवा वर्ग का आंदोलन के कथानक का अल्पविराम है। प्रथम और आगामी चरण के मध्यवर्ती अंतराल में स्वाभाविक तौर पर हमें यह सोचना होगा कि हम इसे क्या कहें - आक्रोश का अपूर्व उत्सव अथवा प्रतिरोध का कारनिवाल? बिलाशक यह बापू के दिये 'यंत्र', और 'मंत्र' (जंतर-मंतर) की ऐतिहासिक जीत है, लेकिन इसका अपूर्व चरित्र इसके लिये नयी संज्ञा की मांग करता है।

गौर करें तो शब्दकोश में इसके लिये कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। यह आंदोलन ही है और आक्रोश की अभिव्यक्ति भी। अगर इसका अंदाज अलग है। इसका चरित्र औपनिवेशिक युग और स्वांत्रयोनत काल के इस तरह के सामूहिक उपक्रमों से सर्वथा भिन्न है। यकीनन जेन-जी आंदोलित और उद्देलित है। उसकी मुद्रियां भिंची हुई हैं, लेकिन उसके भीतर किसी के लिये घृणा, बैर अथवा वैमनस्य नहीं है। जंतर-मंतर पर उसका हुजूम मतवालों की अलमत्त टोलियों सा नजर आता है। आंदोलन का यह पैटर्न विश्व में नया है। दिल्ली का जेन-जी आंदोलन ढाका या काठमांडू और बरसात पहले के बीजिंग के थ्येन-आमन आंदोलन से अलहदा है। वह हिंसक या अराजक नहीं है। जंतर-मंतर का आंदोलन गांधीवादी मूल्यों की महत्ता और प्रभाव की दिलचस्पी मिलाए है। इसकी रगों में अन्याय के प्रतिकार के साथ ही सत्य और अहिंसा की भावना प्रवाहमान है। मजेदार बात है कि इसका अंदाज या चरित्र कुछ ऐसा है कि शब्दकोश न्यून हो गया है। क्या इसे आक्रोश का उत्पन्न नहीं? नहीं, उत्सव या जश्न तो अंतिम चरण की सफलता के बाद का

प्रसंग होता है। तो क्या हम इसे प्रतिरोध का कार्निवाल कह सकते हैं?

आंदोलन को पहली सफलता छत्तीस दिन बाद मिली। छत्तीस दिन कम नहीं होते। कैलेंडर के पन्नों के फफड़फड़े के साथ ही आंदोलन हॉकों लगाता है। धैर्य चुकने से आंदोलन बेपटरी भी हो सकता है, लेकिन जंतर-मंतर का संघर्ष डिगा नहीं, इस लौह में मेन स्ट्रिम मीडिया फिर कर्तव्यच्युत दिखा, साबित होसा। गैर-पेशेवर किटारों ने पल-पल की तस्वीरें जुटायीं और हर कोण से चीजों को पेश किया। इस भूमिगत से मुझे जेपी आंदोलन और अपने भूमिगत दिनों की याद हो आयी। मुझे जन्मदिन दिवकर की 'सिंहासन खाली करो' कि ज़रूत आती है' और डॉ. धर्मवीर भारती की 'मुनादी' कविता की याद आई। मुझे ताबडतोड गिरफ्तारियां याद आई, लेकिन जंतर-मंतर रक्त से मुझे नये सबक मिले। यह पाठ रागों में रल का संचार करता है कि जेन-जी या युवा पीढ़ी सचेत है। एक बारगी दूश्यों को याद करो। कोई झंडा या बैनर नहीं, मगर बच्चे हैं कि चले आ रहे हैं। स्वतंत्र-भारत के इतिहास में यह पहला आंदोलन है, जिसमें लड़कियों ने इतनी तादाद में स्वयं स्फूर्त शिरकत की। कोई 'ईसेंटिव' नहीं, कोई फंडिंग नहीं। वे अभिभावकों को बिना बताये छिपकर आईं। उन्होंने अमोर-गरीब, मजदूर-किसान सबको योद्धा में

बदल दिया था। उनकी जंग सत्य और सत्ता की
जंग थी। गांधी जिसे आमबल कहते थे, सच ही
आंदोलन में जतन देखने को मिला। जाति-धर्म,
जैसे-जैसे, छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं। कोई
छोटीनाझपटी, छेड़छाड़ का प्रसंग नहीं। देखें तो लगे
कि बच्चे दिलजोई या तफदीर करने चले आ रहे
हैं। लेकिन नहीं, वे खोट और खुरदरप्रस्त शिक्षा
व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। आंदोलन की तासीर
देखिये। दमन, प्रताड़ना और बेरुखी के बावजूद
गुलिकसर्माथी तक को गुलाब के फूल, पानी बाटलें
और फूड पैकेट ऑफर किये गये और ऐसे संजोधन
व नारे सुने गये, जिससे वे शर्मसार हो जायें।
प्रदर्शनकारियों के लिये फूड, पानी बॉटल्स,
डस्टबीन और प्री सेफ के दूर-दूर यहां तक कि
विदेशों से ऑर्डर किये गये। धरना स्थल पर गाने-
बजाने, पैरोडी मिमिक्री और कोरस-गान के दृश्य
थे। बापू से जब एक विदेशी सवाददाता ने पूछा था
कि बापू आपका अपने दुश्मनों के लिये क्या संदेश
हैं, तो बापू ने कहा था -मेरा तो कोई दुश्मन हीं
नहीं है।' आंदोलन ने लोगों के मन से डर या हौबा
निकाल दिया।

इस आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को यह सिद्ध करने में मदद की कि गांधी इस महोदश की रणनीति में हैं। बापू ने कोर्ट-कोर्ट जनों में जो लो-बाली थी, वह अभी बुझी नहीं है। सत्ता ने गलतियाँ कीं। उसने संवाद की अहमियत को बिसरा दिया। 20 जुलाई को पुलिस की बर्बरता ने सत्ता की छवि कलुषित की और आग में घी का काम किया।

बच्चों की साहसिक सहनशीलता ने माँ-पिताओं और बड़े-बूढ़ों को जंतर-मंतर पहुँचने का प्रेरित किया। बेटे-बेटियों का आचरण धिक्कार का हेतु बना। इस आंदोलन ने कड़ियों को कलाई खोल दी। इसमें अन्वत्य रहे सोमन वांग्चुक। निजी अस्पताल में सत्तापक्ष के हाथों जुस पीकर उन्होंने जिस प्रकार अनशन तोड़ा, उससे उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची। रही सही कसर उनके इस आशय के बयान ने पूरी कर दी कि वह लद्दाख के उराज्यपाल विनय सिन्हा के कहने पर सीजेपी के आंदोलन में शरीक हुये।

राहुल और अखिलेश के बारे में वांगचुक-दंपति के बयान भी गैर जरूरी हैं। जहाँ तक सीजेपी का प्रश्न है, सीजेआई की टिप्पणी से यकबयक जमीन सीजेपी और उसके नेताओं को और और इम्तजान देने होंगे। जेपी और अन्ना आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में प्रतिपक्ष और बौद्धिकों के मन में ढेर सारा संशय है। यह अकारण नहीं है कि केजरीवाल को आंदोलनकारियों की ओर से कोई भाव नहीं मिला, जबकि जेएनयू की ओर बोरा संघर्षचैता नेत्री बनकर उभरी।

राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे दौर में साहस और सतर्कतापूर्वक कदम उठाये, से उनका सार्थक संवाद उन्हें भविष्य में जमीन मुहैया कर सकता है। राहुल सुखियों में रहे, अलबत्ता उन्होंने औरों को 'स्पेस' दिया और फ्रेम में अकेले रहने से परहेज बरता। वह आगे आंदोलन के हिमायती हैं। मोदी को भारत का

अतीत बताते हुये उनकी यह टिप्पणी आगे भी कौंधती रहेगी कि पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर प्यर आतीत भविष्य का मुकाबला कर सकता है? यह जगत-मंजर आंदोलन को सफलता है कि उसमें सारे देश को डूबेलित कर दिया है। प्रदर्शन की आंच विशेशों तक में पहुंच गयी है। बौद्धिक प्रायः जेन-जी के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार कौंसिल उनके साथ है। दिल्ली के वेधशाला ने भारतीय राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है।

दिल्ली पुलिस की किरकिरी हुई है। प्रसंग अवांतर है।
पुणे में एस्परी कांचले ने पुलिस बल को युवक
पर कर्टड बल प्रयोग नहीं करने का ऐलान किया
तो छात्रों ने 'दिल्ली पुलिस हाय-हाय, पुणे पुलिस
आई लव यू' के नारे लगाये। यह 'फ्यूजन' का
दौर है। जेन-जी के आंदोलन में भी कई चीजें
घुलमिल गयी हैं। जंतर-मंतर के असमाप्त
आंदोलन का चरित्र भी इसी 'सायुज्य' की देन है।
उसमें सत्य भी है, सविनय अवज्ञा भी है, अन्याय
के प्रतिकार का संकल्प है और प्रेम और अहिंस
भी। जेन-जी भारत का भविष्य है। उसके समुने
आशाएं और उसकी चिंताएं सारे भारत के लिए
मानने रखती हैं। रिसर्तों का यह कथाकांक्ष मुल
मकसीम गोर्की की कहानी 'सीला मातिरी'
(मातृशक्ति) की याद दिलाता है। सत्य और सत्ता
की मुसलसल जंग में अभी यह देखा जाना शेष है।
कि आंदोलन के आगे के चरणों में सत्ता क्या रवैय
अखियावर करती है?

डॉ. कलाम की पुण्यतिथि पर विशेष

शिवकुमार शर्मा

लेखक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।



मा नवता के सच्चे सेवकों के लिए ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, लगन, अटूट श्रम, सच्ची राष्ट्रभक्ति ही धर्म हैं, हमें हैं और उनका क विद्रुता व राष्ट्र सेवा में समर्पण ही उनका क सबसे बड़ा अलंकरण-आभूषण होता है। ऐसे संत-फक्रद्वाँ के लिए अमीरी-गरीबी, धर्म, मजबूत और पंथ कोई मायने नहीं रखते, सुविधाओं-सुविधाओं कहीं आदे नहीं आती हैं, ऐसे दृढ़ संकल्पी इन संसे परे होते हैं तथा वे ही फर्श से अर्श या सिफर से शिखर तक की यात्रा पूरी कर अनन्तकाल तक समाज के प्रेरणापुंज बने रहते हैं। इसका जीवन्त उदाहरण से भारत रत्न डॉ. ए.पी. अब्दुल कलाम साहब.उनका पूरा नाम अबुल फकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए बचपन में अखबार बेचने का काम किया। छोटी

आयु में काठन परिश्रम करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, किंतु इसी संघर्ष ने उन्हें आत्मनिर्भर और कर्मठ बनाया। प्रारम्भिक शिक्षा रामेश्वरम में प्राप्त करने के बाद उन्होंने। मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एग्रीगेट्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। भारतीय वायुसेना में पायलट बनाना चाहते थे। वे चयन प्रक्रिया में नौवें स्थान पर रहे, जबकि केवल आठ अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुःख था किंतु उन्होंने निराश न होकर वैज्ञानिक बनने का मार्ग चुना और आगे चक्कर पूरे देश का गौरव बने। वर्ष 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) में वैज्ञानिक के रूप में कार्य आरम्भ किया और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से जुड़ गए। वहाँ उन्होंने भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान एस एल वी-3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके माध्यम से 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलता - पूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया।

डॉ. कलाम ने भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल विकास हुआ, जिसके कारण उन्हें 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' कहा गया।

वर्ष 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के लिए यह अद्भुत और अनुपम संप्रयोग ही था कि स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उसी समय डॉ. नरसिंह कर्माकर वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 2007 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उनके पास निजी संपत्ति के नाम पर कुछ पुस्तकें, कपड़े, एक वाीणा और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएँ ही थीं। उनका जीवन सादगी और नैतिकता का आदर्श उदाहरण था। अपनी सादगी, विनम्रता तथा युवाओं के प्रति विशेष लगाव के कारण वे 'जन्ता के राष्ट्रपति' के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे विद्यार्थियों को बड़े सप्ते देखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए निरंतर प्रेरित

करते थे।
 ऋषिपति पद छोड़ने के बाद भी वे शिक्षण, लेखन
 और युवाओं के मार्गदर्शन में सक्रिय रहे। कलाम
 साहब ने विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रनिर्माण और युवाओं
 के मार्गदर्शन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण
 पुस्तकें लिखीं। वह कहते थे कि 'सपने वे नहीं
 होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं
 जो आपको सोने नहीं देते।' महान कर्मयोगी
 कलाम साहब ने यह कदम दिखाया।

7 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय उन्हें हृदयाघात हुआ वह महानायक हम से विदा हो गया। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम, सादगी और गणसेवा का अनपम उदाहरण है।

अ. कलाम को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि डॉ. सी.सी. रमन को 1952 में भारत रत्न से नवाजा गया था इसके पश्चात एक लंबे अरसे के बाद 1997 में किरीसी वैज्ञानिक को यह सम्मान प्राप्त हुआ।

तपोनिष्ठ राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक

स्वामी, सुबह सवैरें मीडिया एल.एल.पी. के लिए
उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16,
अल्हा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-
453555 से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलेजी,
बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subhassaverenews@gmail.com

**‘सुबह सवेरें’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।
इन्हें समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।**

न्याय और कानून

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



वॉर्म बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 16 जुलाई को प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणेश मूर्तियाँ बनाने वालों से पूछा कि क्या उनके व्यावसायिक फायदे पर्यावरण की सुरक्षा और समाज के व्यापक हितों से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की डिवीजन बेंच ने यह बात जनहित याचिका पर बहस के दौरान कही। इस याचिका में प्राकृतिक जल निकायों में प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियों के विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है, भले ही उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्ति बनाने वालों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से बात करते हुए न्यायालय ने कहा कि क्या लोगों के एक समूह का हित समाज के हित से ऊपर हो सकता है? न्यायालय ने निर्माताओं से प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने का भी आग्रह किया। न्यायमूर्ति गडकरी ने पूछा कि मूर्ति बनाने वाले प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के इस्तेमाल पर जोर देने के बजाय ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते जिनसे प्रदूषण न हो।

उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी ऐसे वैकल्पिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण न हो। बेंच ने इस तथ्य पर गौर किया कि पिछले साल पूरे महाराष्ट्र में प्राकृतिक जल निकायों में छह फीट से ज्यादा ऊंची 31,000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां विसर्जित की गईं। खंडपीठ ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विसर्जन से जल निकायों में प्रदूषण होना तय है, भले ही राज्य की नीति अगले दिन मूर्तियों को हटाने की हो। याचिकाकर्ता रोहित जोशी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की 2025 की नीति, जो प्राकृतिक जल निकायों में छह फीट से ज्यादा ऊंची प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति देती है, वह केवल मार्च 2026 तक लागू रहने के लिए थी। इसके बाद पूरी तरह से रोक लगाने की योजना थी।

उन्होंने कहा कि राज्य का रुख उसकी अपनी स्टडी के विपरीत है। इससे पता चलता है कि प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियाँ आसानी से नहीं चुलती हैं। उन पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जहरीले होते हैं।

डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन

कर्मयोगी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वसीम बरेलवी की शायरी को भारत और सीमाओं से परे, जो अपार लोकप्रियता मिली, वह अभूतपूर्व है। विस्तृत हिंदी और उर्दू की दुनिया प्रो वसीम बरेलवी की खूबसूरत शायरी और व्यक्तित्व की मुरिद है। पिछले दिनों प्रकाशित 520 पेज का ग्रंथ ‘वसीम बरेलवी: जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा’ संकलन प्रकाशित हुआ। संकलन में वसीम बरेलवी के रचनाकर्म, जीवन यात्रा, साक्षात्कार आदि साहित्यिक विधाओं में देश के शीर्ष शायरों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की 58 रचनाएं संकलित हैं। डब्ल्यू.बीएस फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रकाशित इस संग्रहणीय अंक के प्रकाशन का श्रेय कंप्यूटर इंजीनियर और साहित्य प्रेमी नीरज जैन को है। निस्संदेह, यह रचना बरेलवी के चाहने वालों के लिए संग्रहणीय है। नीरज जैन को अपनी चौथी संतान बताते हुए पुस्तक में वसीम बरेलवी आत्मीयता के साथ लिखते हैं ‘ 15 जनवरी 2023 में कार हादसे के बाद नीरज ने मेरी जैसी सेवा की, वैसे कोई आज़ाकारी बेटा ही कर सकता है। मेरे बच्चे तो बाहर हैं, नीरज जी मेरी सांसों की पहरेदारी का दायित्व संभाले हुए हैं। मेरा रुआं-रुआं उनके और उनके परिवार के लिए दुआ है। ऐसी निस्वार्थ और समर्पित संतान जिसे मिल जाए वो क्यों न खूबी-ए-किस्मत पे अपनी नाज करे। खुदा इन्हें शाद रखे, आबाद रखे।’

नीरज बताते हैं कि वसीम साहब की शायरी को पढ़ने व सुनने का अनुभव ऐसा है कि जैसे हम एक साथ कबीर, मीर, गालिब और जायसी को पढ़ रहे हों। उनकी रचनाओं में इतनी गहराई और विविधता है कि वे समय व पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर जाती है। वसीम बरेलवी का साहित्य मिलना मेरी ज़िंदगी की एक असाधारण घटना थी। मैंने वसीम साहब से बातचीत में महसूस किया कि वे जीवन के जटिल विषयों को कितनी सहजता व सरलता से समझा देते हैं। उनके सानिध्य ने मेरे दृष्टिकोण को इतना

पर्यावरण की सुरक्षा करना हर हाल में जरूरी

भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने वाले प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के इस्तेमाल पर जोर देने के बजाए ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, जिनसे प्रदूषण न हो। किसी ऐसे वैकल्पिक मटेरियल का इतनी बड़ी संख्या में विसर्जन से जल निकायों में प्रदूषण होना तय है, भले ही राज्य की नीति अगले दिन मूर्तियों को हटाने की हो। प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्तियाँ आसानी से नहीं चुलती हैं। उन पर इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जहरीले होते हैं। जबकि, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इको-फेंडली मूर्तियों को अपना चुके हैं। खासकर छह फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों में।

उन्होंने कहा कि उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य नीति के तहत किए गए वादों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है। प्लास्टर ऑफ़ पेरिस मूर्ति बनाने वालों के संगठन की ओर से पेश अभिभाषक ने न्यायालय से आग्रह किया कि मौजूदा नीति को एक या दो साल और जारी रहने दिया जाए, ताकि लोगों को पसंद में धीरे-धीरे बदलाव हो सके। उन्होंने ऐसे आंकड़ों का जिक्र किया जिससे पता चलता है कि इको-फ़ेंडली मूर्तियों के ऑर्डर 2023 में लगभग 3,000 से बढ़कर पिछले साल 7.8 लाख हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच रातों-रात नहीं बदल सकती।

राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने न्यायालय को बताया कि बड़ी संख्या में भक्त पहले ही इको-फ़ेंडली मूर्तियों को अपना चुके हैं। खासकर छह फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों में। उन्होंने कहा कि पिछले साल विसर्जित की गई छह फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली 13,000 से ज्यादा मूर्तियां इको-फेंडली थीं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के सामने मुख्य मुद्दा प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित की जाने वाली बड़ी मूर्तियों से जुड़ा है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 48 ए निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 ए में प्रावधान है कि प्रत्येक

नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। अधिनियम का विस्तार क्षेत्र। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य



सहित पूरे भारत में लागू है। केंद्र सरकार की शक्तियाँ इस अधिनियम में केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, उसका निषेध या विनियमन करने की शक्ति तथा बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा प्रदूषक उत्सर्जन पर प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति या संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन। कोई

भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा। इसके अलावा प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ भी है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने, ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिये किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देने तथा केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने का भी अधिकार है। सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति। किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिये केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकती है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न

करना या उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। इस अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण है। यहाँ व्यापक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई। अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिये की गई थी, जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाता है। हालाँकि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के साथ को अपयोंत पाया गया है। इससे पर्यावरणीय मामलों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिये एक संस्था की मांग बढ़ गई। इस कारण पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। इसके अलावा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण छह अन्य कानूनों के तहत दीवानी मामलों को भी सुलझाता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन, 1989, रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 1992, जैव विविधता पर कन्वेंशन, 1992, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1994, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट (1983) और द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन, 1994 में भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है।

सृजन के मानवीय सरोकारों के पैरोकार

सकारात्मक बना दिया कि मेरे जीवन में अप्रत्याशित और अविश्वसनीय परिवर्तन हुए। साहित्यकारों व विभिन्न विधाओं में सृजनकारों की नीरज जैन द्वारा मदद का यह पहल किस्सा नहीं है। वे गाहे-बगाहे साहित्यिकारों की मदद के लिये आगे आते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे शुष्क विषय के दक्ष इंजीनियर नीरज जैन साहित्य की सरस धारा के साथ लगातार डूबते-उतरते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे व कवि सम्मेलनों व साहित्यिक संवाद आयोजनों में वे बेहद सक्रिय रहते हैं।

नीरज जैन की साहित्यकारों की मदद की एक प्रेरणादायक घटना का जिक्र कला-संस्कृति के मर्मज्ञ

रचनाकार राजेंद्र शर्मा बताते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को कथाकार बल्लभ डोभाल के 97वें जन्मदिन के अवसर पर कवि, लेखक, पत्रकार उनके नोएडा के सेक्टर 12 स्थित आवास पर बधाई देने पहुंचे तो पत्नी और जवान पुत्र के आकस्मिक निधन से दुखी बल्लभ डोभाल ने कहा कि मेरा जन्मदिन क्यों मना रहे हो, मैं तो सरकारी कागजों में मर चुका हूं।

बल्लभ डोभाल की यह बात सुन सभी स्तब्ध रह गये। कथाकार बल्लभ डोभाल ने दुखी मन से बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रकाशन विभाग उनके दो बाल उपन्यास चालीस सालों से प्रकाशित कर रहा है किन्तु



साल 2018 में प्रकाशन विभाग से उनके पते पर पत्र आया कि उक्त दो बाल उपन्यासों की रायल्टी देय है और चूंकि बल्लभ डोभाल की मृत्यु हो चुकी है, अतः रायल्टी की धनराशि प्राप्त करने के लिए उनके वारिस बल्लभ डोभाल डेथ सर्टिफिकेट और कोर्ट द्वारा प्रमाणित बल्लभ जी की वसीयत (विल) की प्रति प्रकाशन विभाग को भेज दें ताकि रायल्टी का भुगतान किया जा सके।

साहित्यकार राजेंद्र शर्मा बताते हैं जीवन भर कहानियां लिखने वाले बल्लभ डोभाल प्रकाशन विभाग के इस रखेये से इतने क्षुब्ध हुए कि आज तक उस पत्र का जवाब तक नहीं दिया और प्रकाशन विभाग ने भी इस संबंध में आगे कोई कार्यवाही करना सुनासिब नहीं समझा। गौरतलब बात यह है कि प्रकाशन विभाग आज भी उनके उपन्यास प्रकाशित कर बिच्री कर रहे हैं। कालांतर साहित्यकार राजेंद्र शर्मा ने नीरज जैन को बताया कि उम्र के दसवें दशक में चल रहे डोभाल जी जीवट के धनी हैं, पर अब वह पहले की भाँति चल फिर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में समाज और संस्थाओं को आगे आकर रचनाकारों का ख्याल रखना चाहिए।

घटना से गहरे आहत नीरज जैन ने महसूस किया कि यह सूचना भयावह है। बल्लभ डोभाल जी की साहित्य के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा है। उनकी कहानियां प्रेमचंद के पुत्र और ‘कहानी पत्रिका’ के संपादक श्रीपत राय प्रमुखता से प्रकाशित करते रहे। आखिर कैसे कोई संस्थान कैसे जीते जी किसी रचनाकार को मृत घोषित कर सकता है। निश्चय ही यह प्रकाशन विभाग की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इस घटना ने नीरज जैन को उद्बेलित किया। वे बल्लभ डोभाल के घर पहुंचे और जीवनोपयोगी वस्तुओं के साथ उनकी आर्थिक मदद की। उन्होंने प्रतिमाह उन्हें आर्थिक मदद देने की वायदा किया। विडंबना यह है कि डोभाल जी के पास एटीएम कार्ड व बैंक सुविधा नहीं है। अतः नीरज जैन ने हर माह उनकी मदद के लिए उनके पास जाने का फैसला किया।

वे नियमित रूप से खाने पीने व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं देने उनके घर जाते हैं।

27 अक्टूबर 1977 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव कुरालसी में जन्मे नीरज जैन को पिता बिजेंद्र जैन व माता श्रीमती सावित्री जैन ने उच्च संस्कार व शिक्षा दी। दादा शिखर चंद जैन के आदर्शों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उम्र के बढ़ना व बड़ौत से प्रारंभिक पढ़ाई के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दक्षता के लिए एशिया के पहले इंजीनियरिंग संस्थान रुड़की विवि (अब आईआईटी रुड़की) व बिट्स पिलानी से एमसीए व एमएस में डिग्री हासिल की। फिर भारत सरकार के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में कसल्टेंट के पद पर काम करते हुए परिवहन प्रोजेक्टों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। जैन जीवन दर्शन के अनुरूप परोपकार व साहित्य के प्रति गहरा अनुराग उनका विशिष्ट गुण हैं।

पिछले दिनों दिल्ली में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर का मासिक कार्यक्रम ‘डायलॉग’ की डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन का रचनात्मक साथी मिला। इसी साल अप्रैल की एक शाम विशेष गरिमा में ढल गई, जिसने राजधानी के कला जगत को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि संवाद और संवेदना की नई जमीन भी तैयार की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से आयोजन को विशिष्ट आयाम दिया। उन्होंने डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन की ओर से पंजाबी साहित्य की मशहूर लेखिका पद्मश्री अजीत कौर और समकालीन चित्रकला की सशक्त हस्ताक्षर अर्पणा कौर को सम्मानित किया। डब्ल्यूबीएस फाउंडेशन के महासचिव नीरज जैन ने इस मंच को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा दी है। सृजन व सेवा के माध्यम से साहित्यकारों के जीवन व समाज कल्याण में जुटे नीरज जैन के प्रयास निस्संदेह अनुकरणीय हैं। वे अपनी रचनाओं में समय की सूक्ष्म अनुभूतियों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

इस्तीफा नहीं, यह युवाओं के धैर्य की जीत है

सामयिक

अजमत

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ सिंहासन जनता से बड़ा नहीं होता। सत्ता चाहे जितनी शक्तिशाली हो जाए, यदि जनता संविधान पर भरोसा रखते हुए अहिंसा के रास्ते पर डटी रहे, तो अंततः उसे सुनना ही पड़ता है। धर्मद्वे प्रधान का इस्तीफा यदि आज देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, तो इसलिए नहीं कि एक मंत्री ने पद छोड़ा है, बल्कि इसलिए कि यह लाखों युवाओं के धैर्य, संयम और लोकतांत्रिक विश्वास की कहानी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

यह कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। 15 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय में हुई एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी ने देशभर में तीखी बहस छेड़ दी। लाखों युवाओं ने इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट की तरह महसूस किया। बाद में स्पष्टीकरण आया कि टिप्पणी का आशय अलग थाऔर उसे गलत समझा गया, लेकिन तब तक देश के युवाओं के भीतर जमा आक्रोश शब्दों से आगे बढ़ चुका था। उसी दौर में

काकरोज़ जनता पार्टी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बनकर उभरा—उस पीढ़ी का प्रतीक, जिसने तय कर लिया कि अपमान का जवाब हिंसा से नहीं, लोकतांत्रिक प्रतिरोध से दिया जाएगा।

फिर दिल्ली का जंतर-मंतर देश की धड़कन बन गया। जो वहाँ पहुँचा, वह केवल धरने में शामिल नहीं हुआ, उसने भारत को उसके सबसे सुंदर रूप में देखा। तपती धूप थी। किसी का पसीना बह रहा था तो दूसरा अपना गमछ बढ़ा देता था। कोई पसीने से न भीगे तो अनजान लोग उसेहवा करने लगते। किसी के पास पानी था तो वह अपना नहीं, सबका था। किसी के टिफ़िन में चार रोटियाँ थीं, तो वह छह लोगों में बाँटी जा रही थीं। कोई रातभर जागकर सुरक्षा देख रहा था, कोई क्रांति के गीत गा रहा था, कोई संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा था। वहाँ कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था, कोई धर्म नहीं पूछ रहा था। पूछा जा रहा था-‘भाई, खाना खाया?’ ‘आओ यहाँ बैठ जाओ?’ ‘दवा चाहिए?’ शायद लोकतंत्र का सबसे सुंदर चेत भी था। पुलिस की बैरिकेडिंग थी। लाठियाँ भी थीं। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ थी-एक-दूसरे पर भरोसा।

उनके मन में गुस्सा था, लेकिन हाथों में पत्थर नहीं थे। पीड़ा थी, लेकिन आगज़ूनी नहीं थी। लाठियाँ थीं,

लेकिन जवाब में हिंसा नहीं थी। वे संविधान लेकर बैठे थे। वे बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। वे गांधी का रास्ता याद कर रहे थे। उनके हाथों में पोस्टर थे-‘निकम्मी सरकार को बदलना है’, ‘शिक्षा का ऐसा हाल खत्म करना है’, ‘कलम से दूर क्यों कुदाल?’ यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति थी।

धीरे-धीरे यह आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, मुंबई सहित देश के लगभग हर हिस्से में युवा एकत्र होने लगे। शायद ही कोई राज्य बचा हो जहाँ से युवाओं ने समर्थन न भेजा हो। विश्वविद्यालयों में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुड़ते गए। गांधीवादी संगठन, नागरिक अधिकार समूह, छात्रसंगठन और लोकतांत्रिक मंच खुलकर समर्थन में आए। सीजेपी सहित अनेक सामाजिक समूहों और स्वयंसेवकों ने कानूनीसहायता, राहत, चिकित्सा और संगठनात्मक सहयोग दिया। यह किसी एक दल का आंदोलन नहीं रहा; यह उस पीढ़ी का आंदोलन रहा, जो अपने भविष्य को बचाना चाहती थी राजनीति ने पहले इसे अनदेखा करने की कोशिश की। फिर इसे छोटा बताने की कोशिश हुई। फिर इसे बदनाम करने की

कोशिश हुई। लेकिन जब लाखों युवाओं कीआवाज़ पूरे देश में गूँजने लगी, तब चुप्पी टूटने लगी।

इसी बीच देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया। उसके बाद भी देशभर में बहस जारी रही। दूसरी ओर जंतर-मंतर से लोग लगातार संवाद, सत्याग्रह और संवैधानिकसमाधान की बात करते रहे। यह केवल सरकार और आंदोलन के बीच की लड़ाई नहीं थी; यह दो रास्तों की लड़ाई थी-एक रास्ता सत्ता के अहंकार का और दूसरा जनता के धैर्य का।

आखिरकार जब धर्मद्वे प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो लाखों युवाओं ने इसे अपनी जीत नहीं, लोकतंत्र की जीत कहा। क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति की हार का उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने उस विश्वास का सम्मान किया कि लोकतंत्र में जनता की शांतिपूर्ण आवाज़ अंततः सत्ता तक पहुँचती है।

इस आंदोलन का सबसे बड़ा नायक कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं, कोई दल नहीं था। सबसे बड़ा नायक वह छात्रथा, जिसने किराया उधार लेकर दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। वह युवती थी, जिसने घरवालों की चिंता के बावजूद जंतर-मंतर पहुँचने का साहस किया। वह साथी था, जिसने लाठी खाने के बाद भी अपने साथी को पानी पिलाया। वह डॉक्टर था, जिसने बिना शुल्क उपचार किया। वह अधिवक्ता था, जिसने

गिरफ्तार युवाओं के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। वह माँ थी, जिसने बेटे से कहा-‘डटे रहो, लेकिन संविधान का रास्ता मत छोड़ना।’

लोकतंत्र संसद से चलता है, लेकिन उसकी आत्मा जनता में बसती है। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल अदालतों की किताब नहीं, जनता का जीवित दस्तावेज़ है। गांधी केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि संघर्ष की आज भी सबसे प्रभावी भाषा हैं। और युवा केवलभविष्य नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं। धर्मद्वे प्रधान का इस्तीफा इतिहास में किस रूप में दर्ज होगा, यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जंतर-मंतर की धूप, उन युवाओं का पसीना, अनजान लोगों काएक-दूसरे को पंखा झलना, लाठी खाने के बाद भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ना और सत्याग्रह पर अडिग रहना-ये दृश्यभारतीय लोकतंत्र की स्मृति में बहुत लंबे समय तक दर्ज रहेंगे। लोकतंत्र की जीत कभी अचानक नहीं होती। वह धीरे-धीरे बनती है-एक कदम से, एक आवाज़ से, एक सत्याग्रह से और एक भरोसे से।

इस बार भी वही हुआ। जीत किसी व्यक्ति की नहीं हुई। जीत लोकतंत्र की हुई।

बरसात के मौसम में लीक से अलीक तक

लंग्य

सुरेश उपाध्याय

लेखक स्तंभकार हैं।



बरसात के आते ही च्यानी चू रहा हैज एक आम शिकायत रहती थी। टपक-टपक बरसने से तेज बौछार तक ‘पानी का चू ना’ लगा रहता था। कच्चे घरों में लगे लोहे के पतरो (टीन शेड) व कवेलू की छतों में यह आम बात थी। खास बात थी, इससे बचाव की और तरीका चू रहे पानी को बाल्टियों में समेटना। घर के बाल्टी, डिब्बे व बर्तन तक इसमें लगाना पड़ सकते थे। इनके पूरे भरने पर पानी बाहर फेंककर फिर से उसी जगह पर रखने की जिम्मेदारी अलग होती थी। मकान पक्का बना तो गर्डर पथर की छत से पानी रिसने लगा, छत के ऊपर बरसाती और टीन शेड का चलन आया। सीमेंट-कांक्रीट की छत के युग में पानी का लीकेज शुरु हुआ और शुरु है वाटर फफिंग भी चलन

में आ गया है। चू ने से लीक की इस यात्रा में चू ना (शब्द) तो विलुप्त हो गया और लीक सर्वव्यापी हो गया है। कूप, बावड़ी तो रहे नहीं और न उनके लिए चिंताएं रही हैं। अलबत्ता बांध, नहरें, तालाब आदि के लीक होने के समाचार गाहे बगाहे आने लगे हैं। इनके निर्माण ने तो व्यवसाय व रोजगार के अवसर दिए ही थे, लीक होने की घटनाओं/ दुर्घटनाओं ने इन आपदाओं में नए-नए अवसर दिए और शीघ्रातीशीघ्र दिए हैं। लीक (बनी बनाई लकीर) पर चलना अर्थात् मान्य परम्पराओं पर चलना एक गुण माना जाता रहा है और रहूड परम्पराओं को चुनौती देने वाले ‘अलीक’ लिखते या कहलाते रहे हैं। मौंटिंगों, बैठकों की चर्चाएं, निर्णय

जिन्हें गोपनीय रहना था या जिनकी सार्वजनिक घोषणा के लिए उचित अवसर की जरूरत रहती थी, वे भी धीरे से प्रचारित/प्रसारित होने लगी और सूजों के हवाले से छपने व विस्तारित होने लगी है। यह प्रक्रिया भी ‘लीक’ की संज्ञा से नवाजी जाने लगी तथा संदेही की खोज व उसको दंडित करने का आधार बनने लगी। लीक की प्रक्रिया में जासूसी का भी प्रयोग किया गया तथा इसका उपयोग बदले भुनाने व निपटाने के लिए भी हुआ ही होगा, ऐसा माना जाता है। परीक्षाओं के दौर में आईएमपी का चलन ट्यूशन टीचर व गाइडों से शुरु हुआ जो कोचिंग क्लासों में आकर और विस्तार पा गया है। परीक्षाओं के दौर में पान व चाय की दुकान पर आईएमपी की उपलब्धता

के समाचार भी आते रहे हैं। शैक्षणिक युग का यह अनुभव नौकरी व कॅरियर की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं तक विस्तार पाता गया है। कोचिंग सेंटरों से लेकर एवजी परिक्षार्थियों तक आधुनिक तकनीक से पेपर लीक होकर अल्प समय में बड़े भूभाग तक आसानी से पहुंचने लगे हैं। ‘पकड़ा जाए वो चोर’ की तर्ज पर जब पेपर लीक की जानकारी और होहल्ला होता तो फिर से परीक्षा हो जाती है। पहले से ही कार्यभार से प्रभावित न्यायालयों के लिए यह एक ओर क्षेत्र बढ़ जाता है। छात्रों व अभिभावकों की परेशानियों, चिंताओं, अवसाद और आत्म हत्याओं की घटनाओं से जो आवेग, आवेश व आक्रोश बना वह ‘लीक’ नहीं हो पाया और एक वृहद आंदोलन देशभर में खड़ा हो गया

है। अनेको ने इसमें योगदान दिया तो बहुतेरों को इसमें अवसर मिला और अपने-अपने तरीके से उन्होंने अवसर का लाभ लिया है या भविष्य में लाभ के रास्ते तैयार किए हैं। देशव्यापी इस उद्देहन से पेपर लीक के विरुद्ध फुलरफुल प्रणाली बनेगी तथा दोषियों को उचित दंड मिलेगा, ऐसा विश्वास है। हनी ट्रेप से लेकर आर्थिक लाभ के लालच में सुरक्षा प्रणाली से जुड़े लीक के समाचार भी आते रहे हैं। लीक (रिसन) के कई क्षेत्र और भी हैं तथा वे देश के अर्थतंत्र को खोखला कर रहे हैं, उस लीक (रिसन) को रोकने के लिए भी ठोस व प्रभावी प्रणाली बने, यह छोटी सी आकांक्षा है, आपकी क्या राय है?

हमारायही संदेश नशा मुक्त होप्रदेश, सेमरीहरचंदमें मानव श्रृंखला बनाकर दिया संदेश

सोहागपुर। प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत समीपवर्ती ग्राम सेमरीहरचंद में मानव श्रृंखला बनाकर एवं नशामुक्ति की निकली जनजागरूकता रैली। नशामुक्ति जन-जागृति अभियान के तहत शासकीय कन्या उमा विद्यालय एवं शासकीय बालक उमा विद्यालय सेमरहरचंद में खेल, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं जनप्रतिनिधियों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। इस, अवसर पर सेमरीहरचंद चौकी प्रभारी एसआई अशोक यादव ने कहा कि किसी प्रकार का नशा परिवार के स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के साथ आर्थिक स्थिति का क्षण होकर घर परिवार की खुशियों नशा ली लेता है। आपने आगे कहा छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि यदि घर, परिवार या आसपास का कोई व्यक्ति नशे की लत का शिकार है तो उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी क्रम में शासकीय बालक उमा विद्यालय के विद्यार्थियों से सामूहिक शपथ लेकर विद्यालय परिसर से पीपल चौक तक जागरूकता रैली निकाली। रैली में छात्र छात्राओं ने नशे के विरोध में नारेबाजी करते समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षक, शिक्षिकों के अलावा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इधर नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी एवं एसआई वृणेश राय ने बताया कि नशे से दूरी है जरूरी,गुड टच बेड टच एवं सायबर क्राइम से संबंधित कार्यक्रम विवेकानंद स्कूल सोहागपुर में सोमवार 11:30 बजे से आयोजित किया गया है।

कान्हा टाइगर रिजर्व से दुखद खबर

ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुए की इलाज के दौरान मौत, रेस्क्यू के वक्त शरीर पर मिले थे चोट के निशान

जबलपुर (नप्र)। कान्हा टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। रिजर्व के बफर क्षेत्र में आने वाले सिझौरा परिक्षेत्र के ग्राम खटोला में एक ग्रामीण के घर में घुसे तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई है। रेस्क्यू के बाद उसे मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकीय निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जब तेंदुआ ग्रामीण के घर में घुसा था, तब रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे उठेकुलाइज किया और सुरक्षित रेस्क्यू किया था। हालांकि, पकड़ने के दौरान ही तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे, जिसके बाद उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देकर मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय भेज दिया गया था। डॉक्टरों की कोशिशें रहीं नाकाम, शनिवार को तोड़ा दम - मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम लगातार तेंदुए की सेहत पर नजर बनाए हुए थी और उसका इलाज कर रही थी, लेकिन गंभीर चोटों के चलते शनिवार को उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तय की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पुष्टि की कि तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। मौत का प्राथमिक कारण शरीर पर आई गुरानी या रेस्क्यू के वक्त की चोटें माना जा रहा है। वन्यजीवों की सुझाव पर उठ रहे सवाल - कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार वन्यजीवों की मौत होने से चिंता बढ़ गई है। इस क्षेत्र में बाघों और अन्य वन्यजीवों की मौतों के मामले को लेकर पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है, जिसके बाद से प्रशासन पर मौतों के आंकड़ों को रोकने का भारी दबाव बना हुआ है।

सोहागपुर में ब्लाक बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, बदलेगी तस्वीर युवाओं को मिलेगा रोजगार: क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह

सोहागपुर ब्लाक बनेगा औद्योगिक क्षेत्र बदलेगी यहां की तस्वीर बदलने से यहां के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र को व्यापार की नई रफ्तार मिलेगी। सोहागपुर नगर एवं क्षेत्र के विकास को नई गति देने की दिशा में सोहागपुर विधानसभा को एक के बाद एक महत्वपूर्ण सीमांत मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद क्षेत्र के मातापुरा वार्ड में रू. 9,15,048 की लागत से सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही व्यायामशाला निर्माण के लिए रू. 5 लाख तथा प्रजापति समाज के सामुदायिक भवन के लिए रू. 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। भवन का निर्माण भूमि उपलब्ध होने के बाद कराया जाएगा। उक्त उद्घार क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने मातापुरा में भूमिका पूजन एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण के अवसर पर कहे। इस अवसर पर इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, वरिष्ठ वकील जेपी माहेश्वरी, प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी गौरव अग्रवाल,उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी कुमार सरोज, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल गहैरया, अभिषेक चौहान, पार्षद गौरव पालीवाल, पार्षद आशीष विश्वकर्मा, पार्षद भास्कर , इंद्र कुमार दीवान, , भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, एल्डरमैन राकेश मंडल, वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर मालवीय, मंडल महामंत्री मिथिलेश ठाकुर, एल्डरमैन नितिन कहार नगर पंचायत परिषद नगर पालिका अधिकारी धर्मेद्र शर्मा,



संजय परसाई, प्रशांत मालवीय, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। क्षेत्रीय विधायक ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार सोहागपुर विधानसभा के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। स सोहागपुर क्षेत्र में औद्योगिक आपने कहा सोहागपुर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन संभावित स्थानों का चयन

कर निरीक्षण किया गया है। सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है। यदि योजना सफल होती है तो किसानों की भूमि का अधिग्रहण उनकी वर्तमान बाजार कीमत से चार गुना अधिक मुआवजे मिल सकेगा। इस भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। मोहासा ओद्योगिक क्षेत्र में करीबन 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आने वाले एक वर्ष में इस क्षेत्र के विस्तार के साथ एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध

हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी

सूंड से उठाकर पटकने के बाद पैर से कुचला, ऑटो चालक की मौत

इंदौर(नप्र)। एमपी के इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में हाथी के हमले से एक ऑटो चालक की जान चली गई। घटना का वीडियो रिविwar को सामने आया जिसमें हाथी एक व्यक्ति को सूंड से उठाकर जमीन पर पटकता और फिर उसे पैर से कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। घायल चालक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में महावत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार शाम करीब 4~18 बजे राजनगर पुलिस चौकी के पास हुई। मृतक की पहचान 49 वर्षीय विजय उर्फ लक्ष्मण राव होलकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हाथी को रोककर उसे गुड़ खिलांना शुरू किया।



और अन्य परिजनो को छोड़ गए हैं। महावत हिरासत में, इंदौर चिड़ियाघर को सूचना भेजी - थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महावत को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही हाथी के संबंध में इंदौर चिड़ियाघर के अधिकारियों को भी सूचना भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी में घटना के समय महावत हाथी को लेकर इलाके में घूम रहा था और भिक्षावृत्ति कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बड़ी मुश्किल से हाथी को मौके से

भोपाल में बदमाशों ने दो कार सहित चार वाहन फोड़े

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हैसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र इलाके में शनिवार-रविवार देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कॉलोनी में खड़े वाहनों को निशाना बनाते हुए उनके कांच पथरों से फोड़ दिए।पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों ने कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, देर

रात दो युवक बाइक पर सवार होकर कॉलोनी में पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे और घरों के बाहर खड़े चार पहिया वाहनों को निशाना बनाया। बदमाशों ने पथरों से एक-एक कर वाहनों के शीशे तोड़ दिए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सुबह जब वाहन मालिक घरों से बाहर निकले तो सीसीटीवी कैमरों ने देर हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, देर

पुलिस ने शुरू की जांच - घटना की सूचना मिलते ही कटारा हिल्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले, जिसमें दो बाइक सवार संदिग्ध वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

सतना (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 22 जुलाई को देवांगना घाटी में छात्रा से हुए सनसनीखेज सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ा सफलता मिली है। मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला को शनिवार शाम एसओजी और बहिलपुरवा पुलिस की संयुक्त टीम ने भर्कूप थाना क्षेत्र के मड़था जंगलों में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी के हाथ

में भी गोली लगी है। दोनों को शिवरामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। 10 राउंड की क्रॉस फायरिंग, दो अवैध तमंचे बरामद - चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे मड़था के जंगलों में आरोपी की घेराबंदी की गई थी। खुद को घिरा देख 50 हजार के इनामी आरोपी जितेंद्र ने पुलिस टीम पर तांबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी, जिससे एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने

आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 राउंड फायर किए। पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह बाइक समेत गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोचकर उसके पास से दो अवैध तमंचे जप्त किए हैं। जंगल में बाॅयफ्रेंड को बंधक बनाकर की थी दरिद्रता - यह खौफनाक घटना 22 जुलाई को घटी थी। सतना की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा अपने 17 वर्षीय बाॅयफ्रेंड के साथ देवांगना घाटी में बैठी थी।

उप मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद समारोह में दी कारगिल वीरों को श्रद्धांजलि

सैनिकों के त्याग और बलिदान से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं : उप मुख्यमंत्री

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सम्मेलन में कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक वीरता और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। सैनिकों के त्याग और बलिदान से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कारगिल युद्ध में वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजीलगाकर कठिनतम परिस्थितियों में देश को विजय दिलाई। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने सेना की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाये। भारत तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। देश की आजादी के समय वीरों ने जो सपने देखे थे उन्हें 2047 तक पूरा करके देश को विश्वगुरु बनायेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून पास करके सबकों समान अधिकार दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश एक विधान एक निशान और एक प्रधान का सपना पूरा किया। हमारे सैनिकों ने कश्मीर से आतंकवाद की जड़े उखाड़ फेंकी विन्‍य्‍यधरा में पूर्व सैनिकों का स्वागत करते हुए हम सबकों बड़ी प्रसन्नता हो रही है। विन्‍य्‍य ने दुनिया को साफेद बाघ दिया है इसके साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना का नेतृत्व करने वाले थल सेना अध्यक्ष जनरल



उपेन्द्र द्विवेदी तथा नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी विन्‍य्‍यन के ही लाल हैं। सेवानिवृत्त के बाद भी सभी पूर्व सैनिक देश के विकास में अच्‍छा योगदान दे रहे हैं। समारोह में श्री प्रदीप जोशी ने कहा कि पोखरन दो की घटना ने हमारे देश की मानसिकता और युद्ध नीति को बदल दिया। कारगिल युद्ध की सफलता ने इस नई रणनीति को सफल सिद्ध किया। समारोह में पूर्व विधायक तथा सेवानिवृत्त सैनिक श्री लक्ष्मण सिंह तिवारी ने कहा कि विन्‍य्‍य क्षेत्र में बड़ी संख्‍या में पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन हैं। रीवा में

सैनिक स्मारक बनाया जाय। समारोह में जनपद अध्यक्ष श्री लालबहादुर सिंह तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। समारोह में नगर निगम के अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल बी.के. चतुर्वेदी, विप्रैडियर डीएस त्रिपाठी, मेजर जनरल बीएस शर्मा तथा बड़ी संख्‍या में विन्‍य्‍य क्षेत्र महाकोशल और छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। समारोह का संचालन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री रमेश पाण्डेय ने किया।

■ **राज्य मंत्री श्री पंवार सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने कुंवर चैनसिंह और उनके साथियों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन**

सीहोर (निप्र)। अमर शहीद कुंवर चैन सिंह के शहादत दिवस पर शासन की ओर से गाड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने अमर शहीद कुंवर चैनसिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि इस दुनिया में अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो देश में लिए जाए उसी का जीवन सार्थक होता है। आज हम सभी ऐसे ही अमर शहीद



वीर कुंवर चैनसिंह और उनके साथियों हिम्मत खां एवं बहादुर खां को श्रद्धांजली दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए बलिदान कर दिया। राष्ट्र में जागरण और चेतना की लहर के लिए स्वयं किसी न किसी

को आगे आना ही पड़ता है। कुंवर चैन सिंह भी उन्होंने वीर शहीदों में से एक थे। कुंवर चैनसिंह को अंग्रेजों की ताकत का पता होते हुए भी वे अंग्रेजों से भिड़ गए, क्योंकि उनका हौसला बुलंद था। उनका बलिदान हमेशा

याद रखा जाएगा। जो देश अपने क्रांतिकारियों के बलिदानों को याद नहीं करता है उसकी नींव हमेशा कमजोर होती है। एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र की बुनियाद में अनेक शहीदों के बलिदान छुपे होते हैं। हमारी वर्तमान और आने वाली सभी पीढ़ियों को अपने अमर शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखना चाहिए और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता में ही राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति निहित है। हमारे देश ने सैकड़ों सालों तक गुलामी का बोझ झेला है। यदि उस समय हमारे देश के लोगों में एकता का भाव होता, तो शायद हमें इतने वर्षों तक गुलाम न रहना पड़ता। हमारे देश में भाईचारे की भावना सदियों पहले से रही, पर कुछ विदेशी आक्रांताओं ने आकर इस

भाईचारे की भावना को कमजोर किया और हम पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया। कार्यक्रम में विधायक श्री सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह के वंशज एवं पूर्व विधायक श्री राजवंदन सिंह, हिम्मत खां बहादुर खां के वंशज श्री जेडएके लोधी, भारत जोड़ो समिति के श्री बलवीर सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राजीव गुजराती, श्री अनूप सिंह, कलेक्टर श्री बालागुरु के., एसपी श्रीमती सोनीक्षा सक्सेना, श्री राजकुमार गुप्ता, श्री सुदीप प्रजापति सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।



समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यशैली ही सुशासन की पहचान है

● **राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है - संभागायुक्त**
● **मोपाल संभागायुक्त ने की राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा**

सीहोर (निप्र)। भोपाल संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने सीहोर जिला पंचायत सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा तथा अविवादित नामांतरण के सभी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण किसी स्थिति में समय-सीमा से बाहर नहीं जाने चाहिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने जिले में संचालित राजस्व संबंधी कार्यों के बारे में संभागायुक्त को जानकारी दी। संभाग आयुक्त ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से गांवों को राजस्व विवादों से मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा ग्राम स्तर पर आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान के प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के

बैठक में यह रहे उपस्थित

उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से सतत संपर्क बनाए रखने तथा किसानों से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील कार्यशैली ही सुशासन की पहचान है तथा इससे आमजन को त्वरित न्याय और बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना, संयुक्त कलेक्टर श्री रविंद्र परमार, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

लिए सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी तथा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रशासन की रीढ़ हैं और प्रत्येक राजस्व प्रकरण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें। संभाग आयुक्त ने सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करने तथा आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए।

सक्षिप्त समाचार

अनुसूचित जाति सीनियर उत्कृष्ट

बालक छात्रावास में जन्मदिवस पर तिथि मोज का आयोजन

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में संचालित शासकीय छात्रावासों में विशेष तिथियों तथा अवसरों पर जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, अधिकारियों तथा नागरिकों के सहयोग से विशेष भोज आयोजित किए जाने निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को अनुसूचित जाति सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास में सहकारिता विभाग की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अंजली खुरे द्वारा बालकों के लिए तिथि भोज का आयोजन किया गया। जिसमें डिप्टी कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बालकों के साथ बैठकर भोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन के विशेष अवसरों को छात्रावासों में रह रहे बालक-बालिकों के साथ मनाने से उन्हें पारिवारिक और स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है तथा उनमें सामुदायिक भावना का भी विकास होता है।

नलजल योजनाओं के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गुरुवार को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी द्वारा जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल और समूह नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की विस्तृत समीक्षा करते हुए संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं प्रगतिरत योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विकासखण्डवार प्रगतिरत और पूर्ण हो चुकी नलजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों को घर पर ही नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को पूर्ण हो चुकी नलजल योजनाओं को शीघ्र हैंडओवर करने और हैंडओवर कार्यों को प्रमाणित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही ना बर्ती जाए। अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर बनी जल समितियों को सशक्त बनाकर योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि एकल नलजल योजना अंतर्गत स्वीकृत 755 योजनाओं में से 642 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 113 योजनाओं में कार्य प्रगतिरत है। इनमें 50 नलजल योजनाओं में 76-99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा 42 नलजल योजनाओं में 51-75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार 11 नलजल योजनाओं में 26-50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। बैठक में गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना, हलाली समूह जल प्रदाय योजना, उदयपुर समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों के प्रत्येक चरण की जानकारी लेते हुए कार्य को गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमारी सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन डॉ. घोरे ने अस्पताल के वार्डों का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे ने 24 जुलाई को मेटरनिटी वार्ड एवं ओपीडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएनसी वार्ड में मरीजों से वन टू वन चर्चा की। इस दौरान मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं के बदले , स्टॉफ द्वारा किसी प्रकार की राशि तो नहीं ली जा रही की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों एवं परिजनों को बताया कि अस्पताल में आपरेशन, दवाइयां, जन्मो एंज्युलेंस से आना-जाना, समस्त सेवाएं नि:शुल्क दी जाती है। आर्थिक लाभ के लिए कोई भी अस्पताल का स्टॉफ राशि की मांग करता है तो उनकी शिफ्ट कर देंगे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लगे डिस्पले नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रभारी सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.घोरे ने सोनोग्राफी कक्ष के निरीक्षण के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। एएनसी कक्ष में निरीक्षण के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा राउंड प्रारंभ नहीं करने पर स्पष्टीकरण लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ओटी का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

■ **नव्या योजना की बालिकाओं ने अंतरजिला किया शैक्षणिक भ्रमण**

औद्योगिक कार्यप्रणाली और रोजगार के अवसरों से हुईं रूबरू

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल, 40 बालिकाओं ने आधुनिक वस्त्र उद्योग को करीब से जाना

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नव्या योजना के अंतर्गत जिले की 40 बालिकाओं का शैक्षणिक एवं औद्योगिक भ्रमण रायसेन जिले की बुधनी स्थित वर्धमान फैब्रिक्स में आयोजित किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य बालिकाओं को औद्योगिक वातावरण से परिचित कराना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के



प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें कौशल विकास एवं रोजगार के विविध अवसरों की जानकारी प्रदान करना था। भ्रमण के दौरान बालिकाओं ने वर्धमान फैब्रिक्स की आधुनिक उत्पादन इकाइयों का अवलोकन करते हुए धागे से कपड़ा तैयार होने तक की संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने अत्याधुनिक मशीनों के संचालन, गुणवत्ता परीक्षण, प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाओं को समझा। उद्योग के अधिकारियों ने वस्त्र

निर्माण क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार, प्रशिक्षण एवं करियर की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए बालिकाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। आईटीआई की प्राचार्या सुश्री कविता चवुवंशी साथ मौजूद रहीं उन्होंने बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए तकनीकी दक्षता अत्यंत आवश्यक है।



व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर 05 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश चंदेल और खाद्य विभाग के अधिकारियों

द्वारा कुबेरेश्वर धाम स्थित होटल, भोजनालय सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 05 दुकानों से 05 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के लिए युवा समन्वयकों की बैठक संपन्न

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे ‘नशे से दूरी है जरूरी 2.0’ अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले के सभी सात ग्रामीण युवा समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री विकास खराडकर ने की। बैठक में श्री खराडकर ने बताया कि कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंडों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत रैली, नशामुक्ति शतथ, खेल गतिविधियाँ, संगोष्ठी सहित विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में श्री महेन्द्र पचलानिया (नर्मदापुरम), श्रीमती चंचा मिश्रा (सोहागपुर), श्री नारायण बाबरिया (सिवनी मालवा), श्रीमती सुष्मा अहिरवार (बाबई), श्री देवेन्द्र उरहा (बनखेड़ी), श्रीमती आरती शर्मा (केसला) एवं श्री प्रीतम सिंह पूर्विया (पिपरिया) उपस्थित रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। जिला खेल अधिकारी श्री विकास खराडकर ने समन्वयकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विकासखंड में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए।

जिला प्रबंधक, लोक सेवा श्री आनंद झेरवार ने किया इटारसी और केसला लोक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण

साफ-सफाई और ऑनलाइन प्रक्रिया पर दिए कड़े निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। सुशासन और पारदर्शी सेवा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन श्री आनंद झेरवार ने इटारसी और केसला स्थित लोक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। श्री झेरवार द्वारा लोक सेवा केंद्र इटारसी के निरीक्षण के दौरान केंद्र की समग्र व्यवस्था और लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई।

निरीक्षण में पाया गया कि कुछ आवेदनों के ऑनलाइन प्रिंट पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं थे। इस पर श्री झेरवार ने ऑपरेटरों को निर्देश दिए



कि सभी ऑनलाइन भरे गए आवेदनों में आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिए जाएं और शत प्रतिशत

ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा केंद्र और शौचालयों में साफ-सफाई और बेहतर

रखने, सभी ऑपरेटरों के यूनिफॉर्म में समय पर उपस्थित रहने, उपस्थिति रजिस्टर को पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदक को आवेदन की पावती देना अनिवार्य है और भरे गए सभी आवेदन अगले कार्य दिवस तक संबंधित कार्यालयों में भेजे जाएं। CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग का विधिवत संधारण कर मांग पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया। लोक सेवा केंद्र केसला में सेवावार संधारित रजिस्ट्रों और आवेदनों की जांच की गई। यहां भी आवेदन की हार्डकॉपी अगले दिन संबंधित कार्यालयों में भेजने,

ऑनलाइन आवेदन और पावती का प्रिंट साफ-सुथरा निकलने के निर्देश दिए गए। श्री झेरवार ने दोनों केंद्रों में सभी सेवाओं की सूची और आवेदन शुल्क की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करने, प्रत्येक आवेदक को पावती देने और ऑपरेटरों को आवेदकों से विवश एवं शालीन व्यवहार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी केंद्रों पर निर्धारित स्टाफ, पेयजल, बैठक व्यवस्था, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, फर्नीचर और प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध हो और उनका सुचारू संचालन हो।

कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निविदा (टेंडर) में निर्धारित पूर्णता तिथि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूर्ण किया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर प्रगति की सतत समीक्षा की जाए, ताकि किसी प्रकार की अनवश्यक देरी न हो। बैठक में सिंवाई संबंधी

परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त श्री बोनोठ ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा समय पर उपलब्ध कराया जाए।

इसके लिए शासन के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण तैयार कर संबंधित जिला कलेक्टरों को शीघ्र प्रेषित किए जाएं, ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में विलंब न हो। संभागायुक्त श्री बोनोठ ने कहा कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए विकास परियोजनाओं को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण करें, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा मानसिक समस्याओं के लक्षणों की समय पर पहचान एवं उपचार के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में मनकक्ष नोडल अधिकारी डॉ. अशी सदफ, नर्सिंग ऑफिसर रेशमा कुर्शी एवं उमंग काउंसलर ममेश राठौर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

